राजस्थान लोक सेवा आयोग
प्रारम्भिक परीक्षा
सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान

राजस्थान के खनिज
राजस्थान में जनसंख्या
राजस्थान में कृषि
राजस्थान में उद्योग
राजस्थान में परिवहन
राजस्थान की मिट्टीयाँ
राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ
Special Fact of Rajasthan
योजनाएँ

राजस्थान के खनिज

- राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से एक सम्पन्न राज्य है। देश में राजस्थान एक प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है।
- देश के कुल खनिज में राजस्थान का लगभग 22 प्रतिशत योगदान है।
- देश के कुल खनिजों में 15 प्रतिशत धात्विक, 25 प्रतिशत आधात्विक एवं 26 प्रतिशत लघु श्रेणी के खनिजों का भी राज्य का योगदान है।
- राजस्थान में वर्तमान में 79 प्रकार के खनिज मिलते है। इनमें से 56 खनिजों का व्यवसायिक दोहन किया जा रहा है। जो कि देश के कुल खनिज उत्पादन का 9 प्रतिशत है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 4.4 प्रतिशत है।
- राज्य से प्राप्त वाले प्रमुख धात्विक खनिज लौह-अयस्क तांबा, केडमियम, सीसा-जस्ता, चांदी एवं मैंगनीज है।
- भारत में मुम्बई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र के पश्चात राजस्थान का दूसरा स्थान है। देश के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 24 प्रतिशत राजस्थान के बाड़मेर जिले से प्राप्त होता है।
- खनिज भंडारों की दृष्टि से यह देश में झारखण्ड एवं मध्यप्रदेश के बाद तीसरा खनिज समृद्ध राज्य है।
- राज्य खनिज संपदा विविधपूर्ण है। इसलिए इसे 'खनिजों का अजयाबघर' की उपमा से अलंकृत किया गया है।
- राजस्थान जास्पर, वोलेस्टोनाइट व गार्नेट (तामड़) का समस्त देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है।
- सीसा, जस्ता, टंगस्टन, जिप्सम, फ्लोराइट, मार्बल, एस्बेटॉस, रॉकफॉस्फेट,फेल्सपार सोपस्टोन एवं चांदी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है।
- राजस्व के अर्जन में विभाग का प्रदेश में पांचवां स्थान है।
- केवल प्रत्यक्ष रूप से ही 4 लाख व्यक्ति तथा अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख व्यक्ति इस उद्योग में कार्यरत है।
- पेट्रोलियम निदेशालय, राजस्थान परिवर्तित निष्पादन आय-व्ययक वर्ष 2015-16 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम की कुल खपत का लगभग 25-30 प्रतिशत ही उत्पादन होता है, शेष खपत विदेशों से आयात पर निर्भर रहती है।
- राजस्थान से वर्तमान में लगभग 1,75,000-1,90,000 बैरल प्रतिदिन खनिज तेल का उत्पादन होने से देश के कुल उत्पादन में राज्य की लगभग 24 प्रतिशत की भागीदारी हो गई है।
- राज्य के जैसलमेर बेसिन में एक ब्लॉक तेल एवं गैस अन्वेषण हेतु NEP-IX में आवंटित किया गया है।
- राज्य में अरावली रेन्ज के पश्चिम में विस्तृत रेगिस्तानी भू-भाग में हाइड्रोकार्बन व लिग्नाईट के भंडार निहित हैं तथा साथ ही पूर्व के हाड़ौती क्षेत्र में भी हाइड्रोकार्बन के भण्डर मिलने की संभावना हे। यह कुल भू-भाग लगभग 1,50,000 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है।

राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज

- सीसा, जस्ता – 100 प्रतिशत
- वालेस्टोनाइट – 100 प्रतिशत
- केल्साइट – 100 प्रतिशत
- जिप्सम – 99 प्रतिशत
- चाँदी – 99 प्रतिशत
- मार्बल (संगमरमर) – 95 प्रतिशत
- सेन्ट स्टोन (बालूका पत्थर) – 92 प्रतिशत
- गेरू (ऑकर्स) – 92 प्रतिशत
- बॉल क्ले – 89 प्रतिशत
- सॉप स्टोन (घीया पत्थन) – 80 प्रतिशत

राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :-

- **धात्विक खनिज** - लोहा, चाँदी, टंगस्टन, मैंगनीज, सीसा दस्ता, जस्ता, ताँबा।
- **अधात्विक खनिज**- एस्बेस्टॉस, वोलस्टोनाइट, वरमीक्यूलाइट, कैल्सपार, सिलिका, रेत क्वार्टज, मैग्नेसाईट, डोलोमाइट, चायना क्ले, बॉलक्ले, फायरक्ले, पन्ना, गार्नेद, जिप्सम, रॉकफॉस्फेट, पादराइट्स, चूना पत्थर, फ्लोर्सपार, बेराइट्स, बेन्टोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर, ग्रेनाइट, व इमारती पत्थर, सोपस्टोन, कैल्साइट, गेरू, नमक, अभ्रक, केओलिन, स्टेट पत्थर।
- **ईंधन खनिज** - लिग्नाइट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस।
- **आणविक खनिज**- लिथियम, यूरेनियम, बेरेलियम, थोरियम, ग्रेफाइट।

राजस्थान के खनिज

खनिज	प्रमुख प्राप्ति स्थान
लौह अयस्क (Ironore)	जयपुर - मोरीजा बनोला क्षेत्र, दौसा - नीमला राइसेला क्षेत्र, झुंझुनँ - डाबला- सिंघाना, नीम का थाना, उदयपुर - नाथरा की पोल, थुर हुण्डेर
सीसा-जस्ता	उदयपुर - जावर, मोचिया, मगरा, राजसमंद - राजपुरा, दरीबा, भीलवाड़ा - रामपुरा-आगूचा, सवाईमाधोपुर - चौथ का बरवाड़ा
ताँबा	झुंझुनँ - खेतड़ी - सिंघाना क्षेत्र, अलवर - खोदरीबा क्षेत्र
चाँदी	चाँदी सीसे व जस्ते के साथ निकलती है।
मैंगनीज	बांसवाड़ा- लीलवाना, तलवाड़ा
वोलेस्टोनाइट	सिरोही, उदयपुर, पाली, रूपनगढ़ (अजमेर)
रॉक Qॉस्Qेट	सर्वाधिक - उदयपुर उदयपुर - झामरकोटड़ा, कानपुर, सीसारमा, बेलागढ़, भींडर। जैसलमेर - बिरमानिया व लाठी क्षेत्र।
टंगस्टन	डेगाना (नागौर), पाली - नाना कराब। सिरोही - आबू, रेवदर।
जिप्सम	सर्वाधिक : नागौर - भदवासी, बिरसर (बीकानेर), हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर।
फ्लोर्सपार	मांडों की पाल (डूँगरपुर),
कैल्साइट	सर्वाधिक : सीकर
एस्बेस्टॉस	सर्वाधिक : उदयपुर में ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर

अभ्रक	सर्वाधिक : भीलवाड़ा-दांता भूणास, टूँका, बनेड़ी, फूलिया आदि क्षेत्रों से।
Qल्सपार	अजमेर
डोलोमाइट	सर्वाधिक : जयपुर
वरमीक्यूलाइट	अजमेर, बांसवाड़ा,
मैग्नेसाइट	अजमेर, डूँगरपुर, नागौर व पाली
बेन्टोनाइट	बाड़मेर,
पाइराइटस	सलादीपुरा (सीकर)
बेराइटस	अलवर (सर्वाधिक)
गार्नेट	राजमहल (टोंका), अजमेर भीलवाड़ा,
ग्रेनाइट	सर्वाधिक - जालौर गुलाबी - ग्रेनाइट - जालौर काला ग्रेनाइट - काला डेरा, जयपुर
चूना पत्थर	सर्वाधिक - चित्तौड़ केमिकल ग्रेड - जोधपुर, नागौर सीमेंट ग्रेड : चित्तौड़गढ़, नागौर स्टीलग्रेड - सोनू (जैसलमेर), उदयपुर।
घीया पत्थर	देवपुर - सालोज क्षेत्र (उदयपुर), चिंदेरिया (चित्तौड़गढ़), जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर टोंक।
कोटा स्टोन	कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़
संगमरमर	सर्वाधिक - राजसमन्द
	सफेद मार्बल : मकराना (नागौर), मोरवड़ (राजसमंद) हरा - उदयपुर काला मार्बल - भैसलाना, जयपुर लाल - धौलपुर। गुलाबी - भरतपुर, बादामी - जोधपुर, सातरंग का - खांदरा गांव (पाली), लाल पीले छींटेदार - जैसलमेर।
सिलिका रेत	सर्वाधिक : बारोदिया, खीमज (बँदी), अन्य: जयपुर -झिर, सांगोद, मनोता, नारायणपुर व एलनपुर (सवाईमाधोपुर)
गेरू	चित्तौड़गढ़ उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर
बालक्ले	बीकानेर (सर्वाधिक), नागौर
पाइराQाईलाइट	उदयपुर
क्वार्ट्ज	अजमेर
केओलीन	चित्तौड़गढ़,
फायरक्ले	बीकानेर (सर्वाधिक), जैसलमेर, अलवर
स्लेट पत्थर	अलवर के रायसलाना, गीगलाना, बहरोड़ मांढण व भोपासर में।
स्वर्ण	राज्य में स्वर्ण भंडार जगपुरा, आनन्दपुरा-भूकिया, तिमारन माता (बांसवाड़ा) व रायपुर, खेड़ा (उदयपुर)
चीनी मिट्टी	बीकानेर - मुढ़, चाँदी, कोटड़ी पालना, सवाईमाधोपुर-रायसीना व वसुव क्षेत्र, अलवर, सीकर - पुरूषोत्तमपुरा।
मुल्तानी मिटटी	सर्वाधिक बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर।
बेरिलियम	उदयपुर
हीरा	केसरपुरा (प्रतापगढ़)
बिस्मथ	नेरदा (नीम का थाना, सीकर)
बॉक्साइट	बेसिलियों, माजोला (कोटा)
एपेटाइट	सीकर, उदयपुर
सैण्ड स्टोन	बंसी-पहाड़पुर (भरतपुर), बीकानेर, धौलपुर, जैसलमेर
यूरेनियम	सर्वाधिक-ऊमरा (उदयपुर) में, खण्डेला, रोहिल क्षेत्र (सीकर), भणास, जहाजपुरा (भीलवाड़ा)
थोरियम	पाली-भद्रावन, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा-सरदारपुरा
लिथियम	अजमेर व राजगढ़
ग्रेQाइट	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर
पन्ना	देवगढ़ से आमेट (उदयपुर व राजसमंद) के बीच एक संकरी पटटी में, कालीगुमान, गोगुन्दा व टिखी क्षेत्र (उदयपुर) अजमेर के राजगढ़, गुडास व बुबानी
पोटाश	नागौर, गंगानगर बेसिन
लिग्नाइट	बाड़मेर - कपूरड़ी, जालीपा, गिरल,
	बोथिया-भरका क्षेत्र बीकानेर - पलाना, बरसिंगसर, चानेरी, गुढ़ा, बिठनोक, हाडला, पानेरी, गंगासर, मोलसर नागौरी - सोनारी, मेड़ता रोड व इग्यार क्षेत्र। मातासुख - कसनाऊ क्षेत्र
कोबाल्ट	खेतड़ी, नागौर
प्राकृतिक गैस	जैसलमेर - घोटारू, (मीथेन व हीलियम गैस) रामगढ़, गमनेवाला, तनोट, डांडेवाला व मनहर टिब्बा
खनिज तेल	सर्वाधिक - बाड़मेर बाड़मेर - नागाणा, कौसलु, नगर जैसलमेर - साधेवाला, तनोट बीकानेर - बागेवाला, तुवरीवाला। बाड़मेर - गुढ़ामालानी, कोसलू व सिणधरी, हनुमानगढ़ - नानूवाला।

ऊर्जा क्षमता

वर्तमान में दिसम्बर, 2015 तक राज्य को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता 1728.10 मेगावाट है जिसमें 6810.79 मेगावाट क्षमता राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम से संबंद्ध विद्युतगृहों एवं साझेदारी परियोजनाओं से, 2894.31 मेगावाट क्षमता एनटीपीसी, एनएचपीसी व एनपीसी के विद्युत गृहों से केन्द्रीय आवंटन के अन्तर्गत, 3552.15 मेगावाट निजी क्षेत्र से, 3160.00 मेगावाट क्षमता पवन ऊर्जा, 97 मेगावाट बायोमास तथा 7666.85 मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा संयंत्रों से उपलब्ध है।

क्र.	परियोजनाएं	दिसम्बर, 2015 तक
1.	**राज्य की स्वयं एंव साझेदारी की**	
	(अ) तापीय	5190.00
	(ब) जल विद्युत	1017.29
	(स) गैस	603.50
	कुल (1)	**6810.79**
2.	**केन्द्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित**	
	(अ) तापीय	732.86
	(ब) जल विद्युत	221.10
	(स) गैस	556.74
	(द) परमाणु	**2897.31**
	कुल (2)	
3.	**आई.आई.ई. सी., आर.एस.एम. एम.एल/निजी क्षेत्र, पवन ऊर्जा एवं बायोमास परियोजना**	
	(अ) पवन ऊर्जा परियोजनाएं	3552.15
	(ब) सौर ऊर्जा परियोजनाएं	766.85
	(स) बायोमास परियोजनाएं	97.00
	(द) तापीय (आईपीपी/निजी)	3160.00
	कुल (3)	**7576.00**
	कुल अधिष्ठापित क्षमता (1+2+3)	17281.10
	प्रतिशत वृद्धि गत वर्ष की तुलना में 2010-13-76%, 2011-12.19%, 2012-19.09%, 2013-17.07%, 2014-10.69%, 2015-8.63	

स्त्रोत : आर्थिक समीक्षा (2015-16) पृष्ठ-84

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न स्त्रोतों का अनुपात अलग-अलग है जिसमें सर्वाधिक योगदान तापीय ऊर्जा का है। राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन में तापीय ऊर्जा (कोयला, गैस, नेप्था, तरल ईंधन आदि) का योगदान 61.02 प्रतिशत (56.32 तापीय + 4.7 गैस) पन विद्युत का योगदान 10.12 प्रतिशत, परमाणु ऊर्जा का 3.2 प्रतिशत, पवन ऊर्जा का 20.25 प्रतिशत, सौर ऊर्जा का 4.43 प्रतिशत तथा बायोमास का 0.56 प्रतिशत योगदान है।

निर्माणाधीन अणुशक्ति केन्द्र

क्र.	परियोजना	उत्पादन क्षमता (MW) में
1.	रावत माता न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट	**सप्तम इकाई - U-I -700 MW - U-II -700 MW - 12वीं योजना**
	कुल स्थापित क्षमता	1400 MW
2.	बाँसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर (प्रस्तावित) (राज.100 प्रतिशत)	**प्रथम चरण -U-I -700 MW - U-II -700 MW**
	कुल क्षमता	- 1400.00 MW

रावतभाटा में राजस्थान परमाणु बिजली घर 6 की कमिशनिंग के साथ ही देश में वाणिज्यिक रिएक्टरों की संख्या बढ़कर 19 तथा कुल स्थापित क्षमता 4560 मेगावाट हो गई है। 19 रिएक्टरों के साथ भारत प्रचालरत रिएक्टरों की संख्या के मामले में यूएसए, फ्रांस, जापान, रूसी फेडरेशन, कोरिया गणतंत्र व इंग्लैण्ड के समूह में शामिल हो गया है। 4560 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता में 1280 मेगावाट की क्षमता केवल एक ही स्थल रावतभाटा पर 6 रिएक्टरों में स्थापित है। देश में चालू परमाणु रिएक्टर निम्न है-

1. रावतभाटा - राजस्थान
2. काकरापारा - गुजरात
3. कैगा - कर्नाटक
4. नरौरा - यूपी
5. कलपक्कम - तमिलनाडू
6. तारापुर - महाराष्ट्र

राजस्थान खनिज नीति - 2015

राजस्थान सरकार द्वारा जनू, 2015 में राज्य की नीवन खनिज नीति जारी की गयी है। इस नीति में खनिजों के विद्रोहन, न्यनूतम अवशिष्ट प्रणाली, अवशिष्ट पुनर्चक्रण, रोजगार सृजन एवं राजस्व प्राप्ति हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं।

इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार है-

- राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिज क्षेत्र के योगदान को क्रमशः बढ़ाना।
- 'खनन क्षेत्र' में राज्य के कुल क्षेत्रफल के वर्तमान प्रतिशत 0.54 को बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत तक करना।
- खनन क्षेत्र में दोहने वाले खनिजों की संख्या बढ़ाकर 57 से 79 करना।
- खनिजों के विदोहन में नवीन तकनीकी का प्रयोग करना।
- खनन क्षेत्र में व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं समावेशी खनन के द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा को तय रखना।

राजस्थान में जनसंख्या

- जनगणना 2011 का नारा- ''हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य''
- जनगणना, 2011 अंतिम आँकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 (लगभग 6.85 करोड़) है, जो देश की जनसंख्या का 5.66 प्रतिशत है।
- वर्ष 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 प्रतिशत रही है।
- राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर (66,26,178) है जबकि जैसलमेर न्यूनतम जनसंख्या (6,69,919) वाला जिला है।
- राजस्थान में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 928 महिलाएँ हैं। डूँगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात (994) वाला एवं धौलपुर न्यूनतम लिंगानुपात (846) वाला जिला है।
- राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। इसमें जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व (595 व्यक्ति प्रति किमी.) वाला तथा जैसलमेर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व (17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.) वाला जिला है।
- राजस्थान में साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता दर 79.2 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 52.1 प्रतिशत है।
- 76.60 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ कोटा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। महिला साक्षरता दर में भी कोटा (65.9 प्रतिशत) प्रथम स्थान पर है।
- राजस्थान में जालौर सबसे कम साक्षरता (55.58 प्रतिशत) वाला जिला है।

राजस्थान की साक्षरता : आजादी से आज तक (1951-2011)

जनगणना वर्ष	साक्षरता	पुरूष साक्षरता	महिला साक्षरता
1951	8.50%	13.88%	2.66%
1961	18.12%	28.08%	7.01%
1971	22.57%	33.87%	10.06%
1981	30.55%	44.77%	14.00%
1991	38.55%	54.99%	20.44%
2001	60.41%	75.70%	49.85%
2011	67.06%	80.51%	52.66%

- वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान राजस्थान में जनगणना नगरों (Census Towns) की संख्या 297 रही।
- देश के 6,40,930 गाँवों में से 44,672 गाँव राजस्थान में हैं उत्तरप्रदेश (1.06 लाख), मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं बिहार के पश्चात राजस्थान देश में गाँवों की सर्वाधिक संख्या वाला पाँचवा राज्य है।
- देश में जिलों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य उत्तरप्रदेश (70), मध्य प्रदेश (50), बिहार (37), महाराष्ट्र (35), राजस्थान (33), एवं तमिलनाडु (32) हैं। देश में जिलों की कुल संख्या 640 है।
- जनगणना - 2011 के दौरान सर्वाधिक तहसीलें जयपुर (13), भीलवाड़ा (12), अलवर (12) एवं उदयपुर (11) जिलों में रही, जबकि सबसे कम तहसीलें जैसलमेर (3) एवं डूँगरपुर (4) जिलों में रही।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 2011 की जनगणना में राजस्थान की साक्षरता में आठ गुना, पुरूष साक्षरता में छह गुना एवं महिला साक्षरता में बीस गुना वृद्धि हुयी है।

जनगणना का तहसीलवार विश्लेषण

- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाली तहसील **गुढामालानी (98.56 प्रतिशत)**
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाली तहसील **जयपुर (4.03 प्रतिशत)**
- सर्वाधिक दशकीय ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाली तहसील **जयपुर (53.24 प्रतिशत)**
- न्यूनतम दशकीय ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाली तहसील **खाजूवाला (3.14 प्रतिशत)**
- सर्वाधिक दशकीय नगरीय जनसंख्या वृद्धि वाली तहसील **बसवा (146.47 प्रतिशत)**
- न्यूनतम दशकीय नगरीय जनसंख्या वृद्धि वाली तहसील **सांगानेर (92.93 प्रतिशत)**
- सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाली तहसील **कुभलगढ़ (1047)**
- न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाली तहसील- **बाड़ी (819)**
- सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाली तहसील-**निवाई (1268)**
- न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात वाली तहसील- **नसीराबाद (780)**
- 0-6 आयु वर्ग में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाली तहसील **कोटड़ा (962)**
- 0-6 आयु वर्ग में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाली तहसील **बुहाना (764)**
- 0-6 आयु वर्ग में सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाली तहसील **रेवदार (945)**
- 0-6 आयु वर्ग में न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात वाली तहसील **बुहाना (785)**
- सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील -**जयपुर (83.89%)**
- न्यूनतम साक्षरता वाली तहसील - **चौहटन (47.14%)**
- सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाली तहसील **-बहरोड़ (80.48%)**
- न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाली तहसील **पीपलखूंट (42.97%)**
- सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाली तहसील **संगरिया (72.69%)**
- न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाली तहसील **-रेवदार (48.81%)**
- वर्ष 2001 से 2011 के दौरान राज्य के छः जिलों चूरू जैसलमेर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बाड़मेर व डूँगरपुर में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में गिरावट आयी है।

सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले

1. जयपुर - 66,26,178
2. जोधपुर - 36,87,165
3. अलवर - 36,74,179
4. नागौर - 33,07,743
5. उदयपुर - 30,68,420

सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि (2001-2011) वाले जिले

1. बाड़मेर - 32.55 प्रतिशत
2. जैसलमेर - 31.8 प्रतिशत
3. जोधपुर - 27.70 प्रतिशत
4. बांसवाड़ा - 26.91 प्रतिशत
5. जयपुर - 26.2 प्रतिशत

न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले

1. जैसलमेर	–	6,69,919
2. प्रतापगढ़	–	8,67,848
3. सिरोही	–	10,36,346
4. बूंदी	–	11,10,906
5. राजसमंद	–	11,56,597

न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले

1. श्रीगंगानगर	–	10.0 प्रतिशत
2. झुंझुनूं	–	11.7 प्रतिशत
3. पाली	–	11.9 प्रतिशत
4. बूंदी	–	15.4 प्रतिशत
5. चित्तौड़गढ़	–	16.1 प्रतिशत

सर्वाधिक जन-घनत्व वाले जिले

1. जयपुर	–	595
2. भरतपुर	–	503
3. दौसा	–	476
4. अलवर	–	438
5. धौलपुर	–	398

न्यूनतम जन-घनत्व वाले जिले

1. जैसलमेर	–	17
2. बीकानेर	–	78
3. बाड़मेर	–	92
4. चूरू	–	147
5. जोधपुर	–	161

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले

1. डूँगरपुर	–	994
2. राजसमंद	–	990
3. पाली	–	987
4. प्रतापगढ़	–	983
5. बॉसवाड़ा	–	980

न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले

1. धौलपुर	–	846
2. जैसलमेर	–	852
3. करौली	–	861
4. भरतपुर	–	880
5. श्रीगंगानगर	–	887

0-6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले

1. जयपुर	–	9,29,926
2. जोधपुर	–	6,06,490
3. अलवर	–	5,87,959
4. उदयपुर	–	5,08,550
5. बाड़मेर	–	5,01,522

0-6 आयु वर्ग की न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले

1. जैसलमेर	–	1,30,463
2. प्रतापगढ़	–	1,50,518
3. बूँदी	–	1,59,884
4. सिरोही	–	1,73,364
5. राजसमंद	–	1,76,041

सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात (0-6) वाले जिले

1. बांसवाड़ा	–	934
2. प्रतापगढ़	–	933
3. भीलवाड़ा	–	928
4. उदयपुर	–	924
5. डूंगरपुर	–	922

न्यूनतम शिशु लिंगानुपात (0-6) वाले जिले

1. झुंझुनूं	–	837
2. सीकर	–	848
3. करौली	–	852
4. गंगानगर	–	854
5. धौलपुर	–	857

साक्षरता दर (जिलो का क्रम)

क्र.सं.	जिला		प्रतिशत में
1.	कोटा	–	76.6
2.	जयपुर	–	75.5
3.	झुंझुनूं	–	74.1
4.	सीकर	–	71.9
5.	अलवर	–	70.7
6.	भरतपुर	–	70.1
7.	गंगानगर	–	69.6
8.	अजमेर	–	69.3
9.	धौलपुर	–	69.1
10.	दौसा	–	68.2
11.	हनुमानगढ़	–	67.1
12.	चूरू	–	66.8
13.	बारां	–	66.7
14.	करौली	–	66.2
15.	जोधपुर	–	65.9
16.	सवाई माधोपुर	–	65.4
17.	बीकानेर	–	65.1
18.	राजसमंद	–	63.1
19.	नागौर	–	62.8
20.	पाली	–	62.4
21.	उदयपुर	–	61.8
22.	चित्तौड़गढ़	–	61.7
23.	टोंक	–	61.6
24	झालावाड़	–	61.5
25.	बूंदी	–	61.5
26.	भीलवाड़ा	–	61.4
27.	डूँगरपुर	–	59.5
28.	जैसलमेर	–	57.2
29.	बाड़मेर	–	56.5
30.	बॉसवाड़ा	–	56.3
31.	प्रतापगढ़	–	56.0
32.	सिरोही	–	55.3
33.	जालौर	–	54.9

सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले

1. कोटा	–	76.60
2. जयपुर	–	75.5
3. झुंझुनँ	–	74.1
4. सीकर	–	71.9
5. अलवर	–	70.7

न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले

1. जालौर – 54.90
2. सिरोही – 55.30
3. प्रतापगढ़ – 56.00
4. बांसवाड़ा – 56.30
5. बाड़मेर – 56.50

सर्वाधिक पुरूष साक्षरता दर वाले जिले

1. झुंझुनूं – 86.9
2. कोटा – 86.3
3. जयपुर – 86.1
4. सीकर – 85.1
5. भरतपुर – 84.1

न्यूनतम पुरूष साक्षरता दर वाले जिले

1. प्रतापगढ़ – 69.5
2. बॉसवाड़ा – 69.5
3. सिरोही – 70.0
4. जालौर – 70.7
5. बाड़मेर – 70.9

सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले

1. कोटा – 65.9
2. जयपुर – 64.0
3. झुंझुनूं – 61.0
4. श्रीगंगानगर – 59.7
5. सीकर – 58.2

न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले

1. जालौर – 38.5
2. जैसलमेर – 39.7
3. सिरोही – 39.7
4. बाड़मेर – 40.6
5. प्रतापगढ़ – 42.4

सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर (प्रथम पॉच) (जनसंख्या लाख में)

1. जयपुर (34.7)
2. जोधपुर (12.64)
3. कोटा (11.76)
4. अजमेर (10.35)
5. बीकानेर (8.0)

ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या (2011)

- राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अंश 75.1 प्रतिशत है जबकि राज्य के 24.9 प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं।
- राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले डूँगरपुर (93.3 प्रतिशत) बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं जालौर है।
- सर्वाधिक नगरीय आबादी प्रतिशत वाले जिले कोटा(60.3%) जयपुर (52.4%) अजमेर, जोधपुर एवं बीकानेर हैं।
- जयपुर राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर हैं। देश के 10 सबसे बड़े नगरों में शामिल जयपुर राज्य की कुल आबादी का 4.48 प्रतिशत एवं कुल नगरीय आबादी का 18 प्रतिशत निवास करता है।

राजस्थान की जनगणना - 2011 : एक विशलेषण

- 50 लाख से ऊपर आबादी वाला एकमात्र जिला -**जयपुर**
- 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिलो की संख्या -**5**
- 20 लाख से अधिक आबादी वाले जिलो की संख्या -**4**
- 30 प्रतिशत से अधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले -**बाड़मेर (32.5 %) एवं जैसलमेर (31.8 %)**
- 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले -**जैसलमेर (6.69%) एवं प्रतापगढ़ (8.67%)**
- 15% से कम दशकीय वृद्धि वाले जिले -**श्रीगंगानगर (10%), झुंझुनूँ (11.7%) पाली (11.9%)**
- 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले -**जयपुर (595) एवं भरतपुर (503)**
- 100 से कम जनघनत्व वाले जिले **जैसलमेर (17), बीकानेर (78) एवं बाड़मेर (92)**
- सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र - **दक्षिणी राजस्थान**
- 850 से कम लिंगानुपात वाले जिले - **धौलपुर (846)**
- 950 से अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कोई नहीं
- 850से कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले - **झुंझुनूँ, सीकर**
- 75 प्रतिशत से अधिक साक्षरता वाले जिले -**कोटा (76.6%) एवं जयपुर (75.5%)**
- सबसे कम साक्षरता वाले जिले -**जालोर एवं सिरोही**
- सर्वाधिक पुरूष साक्षरता (70% से अधिक) वाले जिले -**झुंझुनूँ, कोटा, जयपुर सीकर, भरतपुर एवं अलवर**
- सबसे कम पुरूष साक्षरता वाले जिले -**प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा**
- 65% से अधिक महिला साक्षरता वाला जिला -**कोटा (65.9%)**
- 60% से अधिक साक्षरता वाले जिले - **कोटा, जयपुर, झुंझुनूँ, (65.9%)**
- 50% से कम महिला साक्षरता वाले जिले -**18**
- 40 से कम महिला साक्षरता वाले जिले -**जालौर, जैसलमेर, सिरोही**
- दस लाख से अधिक आबादी वाले नगर - **(जयपुर जोधपुर, कोटा, अजमेर)**
- पाँच लाख से अधिक आबादी वाले नगर -**पाँच (जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर)**
- ऐसा सबसे बड़ा नगर जो जिला मुख्यालय नहीं है -**ब्यावर**
- राज्य की कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या का अंश -**1/4**
- राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले -**जैसलमेर एवं बाड़मेर**
- वे जिले जिनकी अभी अधिक आबादी नगरों में निवास करती है -**कोटा एवं जयपुर**
- जयपुर जिले में राजस्थान की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना अंश पाया जाता है। -**1/5**

- राज्य की कुल आबादी का सर्वाधिक अंश (9.7%) जयपुर जिले में एवं सबसे कम अंश (1%) जैसलमेर जिले में पाया जाता है।
- 2001-2011 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि जैसलमेर (+32), भरतपुर (+27), कोटा (+22), धौलपुर (+20), बारां (+20), झालावाड़ (+19), बूँदी (+16), टोंक एवं प्रतापगढ़ (+8), जयपुर एवं बाड़मेर (+6), अलवर, सवाईमाधोपुर, दौसा एवं भीलवाड़ा (+5), करौली (+4), पाली एवं बाँसवाड़ा (+3) तथा जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ (+1) जिलों में दर्ज की गयी।
- 2001-2011 के मध्य लिंगानुपात (Sex Ratio) में सर्वाधिक नकारात्मक या घटने की प्रवृत्ति डूँगरपुर (-35), उदयपुर (-20), चुरू (-16), जालोर (-15), राजसमंद (-14), सिरोही (-9), सीकर (-7), नागौर (-3) तथा बीकानेर एवं झुंझुनू (-1) जिलों में दर्ज की गयी।
- 2001-2011 की अवधि में राजस्थान के सकल लिंगानुपात में 3 अंको की वृद्धि दर्ज की गयी।

जनगणना 2011 के अंतिम ऑकड़ों के अनुसार राज्य की संभागवार स्थिति

क्र	संभाग	जिलों के नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	जनसंख्या 2011(लाखों में)	विशेष विवरण
1	जयपुर	जयपुर, सीकर, झुंझुनूँ, अलवर, दौसा (5 जिले)	36615	167.49% (24.43%)	सर्वाधिक जनंसख्या, सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक अनुसूचित जाति (SC) जनंसख्या, सर्वाधिक साक्षरता।
2	जोधपुर	जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर (6 जिले)	117800 (34.42%)	118.63 (17.31%)	सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर।
3	बीकानेर	बीकानेर चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ (4 जिले)	64708	81.47 (11.89%)	सर्वाधिक (SC) अनुसूचित जाति-जनसंख्या अनुपात %
4	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक (4 जिले)	43848	97.21 (14.33%)	राज्य का मध्यवर्ती या केन्द्रीय संभाग
5	उदयपुर	डदयपुर, डूँगरपुर बाँसवाड़ा, राजसमंद चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ (6 जिले)	36942	98.23 (14.33%)	सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक लिंगानुपात
6	कोटा	कोटा, बूँदी, झालावाड़ बारां (4 जिले)	24204	56.96 (8.31%)	न्यूनतम जनसंख्या।
7	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली सवाईमाधोपुर (4 जिले)	18122 (5.3%)	65.49 (9.55%)	न्यूनतम क्षेत्रफल।

-

राजस्थान में कृषि

- राज्य में 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।
- देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का राज्य में लगभग 11 प्रतिशत
- देश के जल संसाधन का राज्य में 1.16 प्रतिशत
- राज्य के कुल कृषित क्षेत्र का 2/3 भाग लगभग 65 प्रतिशत खरीफ के मौसम में।
- बीहड़ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र धौलपुर (कुल क्षेत्रफल का 19 प्रतिशत)
- कृषि का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 24-30 प्रतिशत
- सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल - श्रीगंगानगर, न्यूनतम -चूरू
- राज्य में देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 10.2 प्रतिशत
- राज्य के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 32.4 प्रतिशत भाग सिंचित।
- बांसवाड़ा में गैर कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग सर्वाधिक।
- राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5 प्रतिशत स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि के अंतर्गत, सर्वाधिक- बाड़मेर एवं न्यूनतम श्रीगंगानगर
- राज्य में बोया गया शुद्ध क्षेत्र सर्वाधिक - बाड़मेर, न्यूनतम- राजसमंद।

राजस्थान में कृषि का वर्गीकरण

किस्म	समय	फसलें	विशेष
खरीफ	बुवाई-जून-जूलाई, कटाई-सितम्बर-अक्टूबर (उन्नालू)	बाजरा,ज्वार,मक्का, मुंगफली, अरण्डी, तिल, सोयाबीन, ग्वार, अरहर, मूँग, मोठ, उड़द, चावल, कपास	कुल कृषि के 60-65 प्रतिशत भाग पर बोई जाती है। 90प्रतिशत खरीफ की फसलें बारानी भाग पर बोई जाती है। जो पूर्णत: वर्षा पर निर्भर ।
रबी	बुवाई-अक्टूबर-नवम्बर- कटाई-मार्च-अप्रैल (स्यालू)	गेहूँ, जौ, सरसौं अलसी,तारामीरा जीरा,अजवायन, चना, सौंफ, इसबगोल, प्याज, लहसून, तम्बाकू, अफीम, आलू, शकरकन्द, गन्ना	विशेषता सिंचित क्षेत्रों व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इनकी पैदावार।
जायद	बुवाई-मार्च-मध्य -जून	तरबूज, खरबूज, ककड़ी,तरकारी, सब्जियाँ,फल आदि।	इसमें शीघ्र पकने वाले फल व सब्जियों की पैदावार होती है।

गेहूँ

- रबी की महत्वूपर्ण फसल।
- सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर।
- राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल।
- अन्य उत्पादक जिले- जयपुर, अलवर कोटा, सवाई माधोपुर।
- मुख्यत: उत्पादन दक्षिणी-पूर्वी राज्य में।
- मिटटी - दोमट।
- किस्में - सोना कल्याण, शरबती, मैक्सिकन सोना,
- राजस्थान- 3765 (सर्वश्रेष्ठ किस्म), कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी।
- वानस्पतिक नाम - टिट्रिकम ऐस्टिवियम।

बाजरा

- उत्पादन तथा क्षेत्रफल में राजस्थान का देश में प्रथम।
- सर्वाधिक उत्पादन - जोधपुर।

सर्वाधिक बुवाई -बाड़मेर

- राज्य के सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल।
- बाजरे का पूर्वी भाग में उत्पादकता पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक।

जौ

- क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से राज्य का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान।
- माल्टा बनाने हेतु प्रमुख खाद्य फसल, देश का एक चौथाई उत्पादन राजस्थान में होता है।
- सर्वाधिक उत्पादन - जयपुर
- सर्वाधिक बुवाई - जयपुर
- शीतोष्ण जलवायु फसल
- दोमट व बुलई मिट्टी उपयुक्त
- किस्में - ज्योति, राजकिरण, RD2035. RD2508

मक्का

- राज्य का देश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम तथा उत्पादन की दृष्टि से आंधप्रदेश के बाद दूसरा स्थान।
- सर्वाधिक उत्पादन - चित्तौड़, सर्वाधिक बुवाई - उदयपुर।
- किस्में - माही कंचन (कृषि अनुसंधान केन्द्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित) माही सुगंधा, माही धवल, सविता, मोती कम्पोजिट, नवजोत, विजय-किरण
- सर्वाधिक उत्पादन बनास बेसिन में।

चावल

- आर्द्र उपोष्ण तथा उष्ण जलवायु पौधा
- सर्वाधिक उत्पादन - हनुमानगढ़
- काली व चिकनी दोमट मिटटी
- माही सुगंधा (कृषि अनुसंधान केन्द्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित)
- किस्में - चम्बल, कावेरी, बासमती, परमल, रतना, जया

ज्वार

- सोरगम व गरीब की रोटी
- शुष्क कटिबंधीय प्रदेश का पौधा
- सर्वाधिक उत्पादन - महाराष्ट्र
- ज्वार से अल्कोहल व बीयर तैयार की जाती है।
- कृषि राज्य के मध्य व पूर्वी भाग में।
- सर्वाधिक उत्पादन -अजमेर
- किस्में - राजस्थान चरी

गन्ना

- उष्ण कटिबंधीय पौधा
- विश्व का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है।
- सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर में होता है।
- श्रीगंगानगर, में गन्ने की कृषि सिंचाई से की जाती है।
- किस्में - रसभरी, श्वेता

मुगंफली

- उष्ण कटिबंधीय पौधा
- सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन- बीकानेर, जयपुर, सीकर, चूरू।
- देश में सर्वाधिक उत्पादन - गुजरात
- लूणकरणसर (बीकानेर) की मूँगफली विश्व भर में प्रसिद्ध, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहते है।
- किस्म - चंदा

अलसी

- देश में सर्वाधिक मध्यप्रदेश
- राज्य में सर्वाधिक उत्पादन -नागौर
- सर्वाधिक बुवाई - चित्तौड़

राई व सरसों

- राज्य का देश में प्रथम स्थान है।
- सर्वाधिक उत्पादन - श्रीगंगानगर
- पीली क्रांति का संबंध सरसों में।
- भरतपुर का इंजन छाप तेल देश भर में प्रसिद्ध।
- सेवर (भरतपुर) में केन्द्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र (20 अक्टूबर, 1963)

सोयाबीन-

- देश में सर्वाधिक सोयाबीन मध्यप्रदेश में उगाया जाता है।
- राज्य के दक्षिण-पूर्वी जिलों में सर्वाधिक उत्पादन।
- सर्वाधिक उत्पादन - झालावाड़।

चैती गुलाब (दमश्क गुलाब)

- नाथद्वारा तथा खमनौर (राजसमंद) में।
- मेवाड़ के महाराणा रतनसिंह के शासन काल में मुगलों से मंगा कर कृषि।
- चैती गुलाब का इत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

खजूर

- बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है।
- खजूर के सूखे फलों को छूहारा कहते हैं।
- किस्में - हिलानी, बाहरी जाहिड़ी।

कांगणी

- दक्षिणी राजस्थान के शुष्क आदिवासी क्षेत्रों की फसल है।
- उपयोग खाने तथा पशुओं के चारे में (रोटी बनती है)।

कपास

- उष्ण कटिबंधीय पौधा
- ग्रामीण भाषा में इसे 'बणीया' कहते है।
- विश्व में भारत का प्रथम स्थान
- देश में सर्वाधिक गुजरात में।
- सर्वाधिक उत्पादन - हनुमानगढ़
- देशी कपास का सर्वाधिक उत्पादन - जयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा।
- मालवी कपास का सर्वाधिक उत्पादन - कोटा, बूँदी, झालावाड़
- इसे सफेद सोना कहते है।
- किस्में-बीकानेरी, नरमा, गंगानगर अगेती।

होहोबा (जोजोबा)

- यह मैक्सिकों, कैलिफोर्निया और एरिजोना के रेगिस्तान मे।
- इसे 'पीला सोना ' कहते है।
- झज्जर (बीकानेर) में जोजोबा कृषि से संबंधित निजी क्षेत्र की राज्य की सबसे बड़ी परियोजना।
- कृषि - जोधपुर, श्रीगंगानगर जयपुर, चुरू।
- इस फलस की खेती को विकसित करने के लिए इजरायली वैज्ञानिकों की सहायता से दो कृषि फार्म-1 फतेहपुर (सीकर), ढण्ढ (जयपुर)
- इसका पौधा सर्वप्रथम काजरी द्वारा 1965 में इजराइल से लाया गया।

अफीम

- अफीम का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में होता है।
- रबी की फसल है इसे काला सोना भी कहते है।
- यह एक नारकोटिक्स फसल है।
- उत्पादन सरकार के नियत्रंण में रहता है।
- कच्चा फल पकने पर डोड़ा कहलाता है।
- बीजों को खस-खस (PoPPy seed) कहते है, जिनका उपयोग तिजारा बनाने में किया जाता है।

राज्य में Qसलों का उत्पादन

फसल	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
चावल	हनुमानगढ़	कोटा	बांरा
ज्वार	अजमेर	पाली	नागौर
बाजरा	जौधपुर	बाड़मेर	अलवर
जौ	जयपुर	अलवर	सीकर
मूँग	नागौर	अलवर	पाली
मोठ	बाड़मेर	जोधपुर	नागौर
उड़द	भीलवाड़ा	बूँदी	झालावाड़
चावल	सीकर	झुंझुनू	नागौर
चना	चूरू	जयपुर	बीकानेर
मटर	नागौर	बूँदी	अलवर
मूंगफली	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर
तिल	पाली	बारा	कोटा
सोयाबीन	झालावाड़	बारा	कोटा
सरसों एवं राई	श्रीगंगानगर	अलवर	भरतपुर
अलसी	नागौर	बांरा	बूँदी
तारामीरा	जयपुर	नागौर	अजमेर
कपास	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	-
गन्ना	श्रीगंगानगर	बूँदी	चित्तौड़गढ़
मक्का	चित्तौड़	भीलवाड़ा	बाँसवाड़ा
गेहूँ	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	अलवर

- राज्य में सर्वाधिक फल - श्रीगंगानगर
- राज्य में सर्वाधिक मसालें - बारां
- छाछिया झुलसा व उकटा जीरा के रोग है।
- सोजत की मेंहदी के अतिरिक्त लाल सुर्ख रंग लिए गिलुण्ड (राजसमंद) की मेंहदी प्रसिद्ध।

कृषि के प्रकार

- **मिश्रित कृषि**- कृषि+पशुपालन, राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर आधारित।
- **शुष्क कृषि** - सुखारोधी किस्मों को उन्नत कृषि विधियों से उगाया जाता है। इसमें वर्षा जल का सुनियोजित संरक्षण करते हुए कम पानी में फसल ली जाती है।
- **झूमिंग कृषि** - पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वृक्षों को काटकर तथा जलाकर वर्षा बीजारोपण द्वारा किया जाता है। जिसे वाला कृषि कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में इसे **चिमाता** तथा मैदानी भागों में इसे **दजिया** कहते हैं। यह कृषि डूँगरपुर, उदयपुर बांसवाड़ा में होती है। इस कृषि का प्रयोग आदिवासियों द्वारा किया जाता है।
- **बागाती/बागानी** - बड़े-बड़े बागानों के माध्यम से व्यापारिक उद्देश्य के लिये नकदी फसले प्राप्त करना, जैसे - चाय, कॉफी, रबर आदि।
- **बारानी कृषि** - वर्षा पर आधारित
- **रिले क्रॉपिंग कृषि** - एक वर्ष में एक खेत में चार फसलें बोना।
- **सोयाबीन कृषि (समोच्च कृषि)**- पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती में की जाने वाली कृषि।

कृषि के क्षेत्र में विभिन्न

क्रांति	संबंध	क्रांति	संबंध
हरित क्रांति	1966-66 खाद्यानों के उत्पादन के तीव्र वृद्धि लाना। जनक- नॉरमन ई. बोरलोग (अमेरिका)। भारत में जनक एम.एस. स्वामीनाथन	नीली क्रांति	मत्स्य पालन में वृद्धि
श्वेत	1970 में दुग्ध उत्पादन से संबंधित जनक-वर्गीज कुरिमन	सिल्वर क्रांति	अण्डा उत्पादन
गुलाबी क्रांति	झींगा पालन व वृद्धि	सुनहरी क्रांति	बगवानी उत्पादन
भूरि क्रांति	फुड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण)	लाल क्रांति	मांस व टमाटर
पीली क्रांति	सरसों उत्पादन (1986-87)	बादामी क्रांति	मसाला उत्पादन
इन्द्रधनुष क्रांति	समस्त क्रांतियों का समन्वय रूप इसे एकीकृत क्रांति भी कहते है, 2000 में प्रारम्भ	राजमार्ग क्रांति	विश्व स्तरीय सड़क निर्माण

राजस्थान की घासें

- सेवण घास - यह अत्याधिक प्रोटीन युक्त घास
- धामण घास - रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशुओं के लिए महत्वपूर्ण।
- करड़ घास - रेगिस्तानी क्षेत्र में
- अंजन घास - हर मौसम में उगले वाली रेगिस्तानी घास।

कृषि के विशिष्ट प्रकार

1. बिटी कल्चर - अंगुरों का व्यावसायिक उत्पादन
2. पीसी कल्चर - मत्स्य पालन
3. सेरी कल्चर - रेशम पालन
4. हॉर्टी कल्चर - फल, फुल व सब्जियाँ उत्पादन पालन
5. फ्लोरी कल्चर - मधुमक्खी पालन
6. फ्लोरी कल्चर - फुलो का व्यवसायिक उत्पादन
7. मैरी कल्चर - समुद्री जीवों से संबंधित
8. वर्मी कल्चर - केंसुआ पालन

कृषि मंडियाँ

1. प्याज मंडी - अलवर
2. अमरूद - सवाईमाधोपुर
3. आंवला मंडी - चौमू (जयपुर)
4. पुष्प पार्क - खुशखेड़ा (अलवर)
5. टमाटर - बस्सी (जयपुर)
6. लहसून - छीपा बड़ौदा (बारां)
7. अश्व गधा मण्डी - झालावाड़
8. मशाला मंडी - जालौर
9. मशाला पार्क - झालावाड
10. धनिया मंडी - रामगंज मंडी (कोटा)
11. हर्बल पार्क - कोटा
12. मिर्च मंडी - टोंक
13. मुंगफली मंडी - बीकानेर
14. मेहन्दी मंडी - सोजत (पाली)
15. फूल मंडी - पुष्कर (अजमेर)
16. जीरा मंडी - जोधपुर
17. सोनामुखी मंडी - सोजत (पाली)
18. मार्बल मंडी - किशनगढ़ (अजमेर)
19. चना मंडी - हनुमानगढ़
20. संतरा मंडी - भवानी मंडी (झालावाड़)
21. किन्नू मंडी - श्रीगंगानगर
22. ईसबगोल मंडी - भीनमाल (जालौर)

कृषि विकास हेतु प्रयासरत संस्थाएँ

1. **राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड :-**
   स्थापना - 6 जून, 1974
   उद्देश्य - कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु। कृषि उपज मंडियों की स्थापना, मंडी प्रांगणों व ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण व रख-रखाव
2. **राजस्थान राज्य सहकारी क्रय - विक्रय संघ लिमिटेड (राज फैड)**
   स्थापना - 26 नवम्बर, 1977
   उद्देश्य - किसानों को उचित मूल्यों पर विभिन्न सहायता प्रदान करना, कृषि उत्पादों की खरीद, बिक्री एवं प्रोसेसिंग की समुचित व्यवस्था करना।
3. **राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स लि. (Spinfed)**
   स्थापना - 1 अप्रैल, 1993
   उद्देश्य - समन्वित आधार पर कपास के उपार्जन, विधायन, उन्नत तकनीकि के प्रयोग तथा उत्पादित सूत आदि की प्रभावी विपणन व्यवस्था।

4. **श्री गंगानगर कॉटन कॉम्पलेक्स :- स्थापना - 1989**
   उद्देश्य - राज्य में कपास उत्पादक किसानों को ' कपास की पैदावार बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना।
5. **तिलम संघ :-**
   स्थापना - 3 जुलाई, 1990
   उद्देश्य - राज्य में तिलहन फसलों की पैदावर बढ़ाने हेतु।
6. **केन्द्रिय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) :-**
   स्थापना - 1959
   उद्देश्य - शुष्क व अद्धशुष्क क्षेत्रों में वन संपदा व कृषि का विकास करने हेतु।
   क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र - पाली, बीकानेर, जैसलमेर, भुज (गुजरात)
   कृषि विज्ञान केन्द्र - पाली, जोधपुर।
   क्षेत्रीय प्रबंध एवं मृदा संरक्षण क्षेत्र - चांदन गांव (जैसलमेर), बीछवाल (बीकानेर)।
7. **राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय :-**
   राज्य में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1962 में उदयपुर में स्थापित किया गया। 1987 में कृषि संकाय उदयपुर से अलग कर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना की गई।
   वर्तमान इसके अधीन 21 जिले। 'स्वामी केशवानन्द राजधानी कृषि विश्व विद्यालय' नया नाम।
8. **महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्व विद्यालय :-**
   उदयपुर दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कृषि शिक्षा व अनुसंधान को अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ान हेतु। इसके अधीन 12 जिले।
   हॉर्टिकल्चर व वानिकी महाविद्यालय - झालावाड़।

अमूल्य नीर योजना

2005 - 06 में प्रारम्भ
राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा
जल का संरक्षण तथा कृषि में जल का कुशलतम उपयोग।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

2005 - 06 में भारत सरकार द्वारा। राज्य के 23 जिलों में।
उद्देश्य - नर्सरी विकास, सब्जी बीज उत्पादन नये बगीचों की स्थापना, जैविक खेती मानव संसाधन विकास।

नवाकुंर

दूरदर्शन के जयुपर केन्द्र द्वारा कृषकों को समस्याओं के समाधान से संबंधित कार्यक्रम।

खेती री बांता व Qोन इन कार्यक्रम

राज्य के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से प्रस्परित।
कृषि संबधी जानकारी दी जाती।
'खेती री बांता' कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक अखबार।

सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना

कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों किसानों को कृषि व अन्य कार्यों हेतु सहकारी ऋण वितरण की सरलता योजना।
देश में सर्वप्रथम राजस्थान में।
29 जनवरी 1999 को।
प्रथम किसान केडिट कार्ड श्री गहलोत द्वारा सिरसी गाँव (जयपुर) के किसान राम निवास यादव को।

तबीजी (अजमेर)

राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र स्थापित।

बकानी (झालावाड़)

राज्य की पहली किसान संघ कंपनी का गठन।

सुरतगढ़ यान्त्रिक कृषि Qॉर्म - (केन्द्रीय कृषि फॉर्म)

सुरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
स्थापना 15 अगस्त 1965
रूस की सहायता से
एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म
उद्देश्य - राजस्थान में कृषि का यन्त्रीकरण करने के लिये फसलों की उन्नत नस्ल विकसित करना।

जैतसर यान्त्रिक कृषि Qॉर्म (केन्द्रीय कृषि Qॉर्म)

जैतसर (श्रीगंगानगर)।
यहाँ पर कपास तिलहन व पशुओं के लिए चारे की खेती की जाती है।
कनाड़ा की सहायता से।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

स्थापना - 16 जुलाई 1929
उद्देश्य - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षत्र में विज्ञान एवं तकनीकि कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का विकास करना।
राजस्थान में ICAR के अनुसंधान केन्द्र।
(A) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्र - बीकानेर
(B) राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र - सेवर (भरतपुर)
(C) काजरी - जोधपुर

मृदा परीक्षण कार्यक्रम (मृदा स्वास्थ्य कार्ड)

- प्रति इकाई क्षेत्र में कम लागत से कृषि उत्पादन बढ़ाना।
- संतुलित खाद एवं उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा देना।
- मृदा में मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्रा के अनुसार फसल की पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संतुलित उर्वरक की सिफारिश देना।
- बायी जाने वाले फसलों के चयन में सहायता करना।
- वर्तमान में राज्य में 33 विभागीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ कार्यरत।
- मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबन्ध की राष्ट्रीय योजना के तहत राज्य के पीपीपी मोड में 12 भ्रमणशील मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाएँ कार्यरत।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

- प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़ आदि), कीट व रोग के कारण नष्ट हुई फसल के बीमा कवरेज के जरिये वित्तीय सहायता प्रदान कर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से चलाई गई योजना हैं।
- इस योजना में ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से बीमित किये जायेंगे एवं गैर ऋणी-कृषक स्वैच्छिक आधार पर योजना में भाग ले सकते हैं।
- मुआवजे की गणना निम्नांकित फार्मूला के आधार पर की जाती है-
- उत्पादकता में कमी *× फसल के लिए बीमित राशि

  गारण्टी उत्पादकता

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (उद्यान विभाग)

- प्रारम्भ :- वर्ष 2010 के (केन्द्र सरकार द्वारा)
- जल की बचत और फसल पैदावार एवं गुणवत्ता में वृद्धि उबड़-खाबड़ या ढालू भूमि पर भी सिंचाई के लिए अनुकूलना, उर्वरकों के दक्ष उपयोग, खरपतवार में कमी, फसल उत्पादन लागत में कमी, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जैसी कुशल पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।

राजस्थान में उद्योग

- राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाईयाँ जयपुर में हैं जबकि सर्वाधिक वृहद् औद्योगिक इकाईयाँ अलवर में स्थापित की गई है।
- राज्य में बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाईयाँ भिवाड़ी (अलवर) में तथा न्यूनतम औद्योगिक इकाईयाँ-जैसलमेर में स्थापित की गई है तो सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ जयपुर व जोधपुर में न्यूनतम जैसलमेर व बाराँ में है।
- राज्य में सर्वाधिक खनन पट्टे संगमरमर के हैं एवं संगमरमर के सर्वाधिक खनन पट्टे राजसमंद जिले को मिले है।
- राज्य में संगमरमर का सबसे बड़ा परिशोधन/प्रोसेसिंग केन्द्र किशनगढ़ (अजमरे) में स्थापित किया गया है।
- राज्य का सबसे बड़ा ग्रेनाइट केन्द्र जालौर में, राज्य में लौहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध जिला नागौर है, तो मलमल के लिए प्रसिद्ध स्थान मथानिया (जोधपुर) है।
- फूल उद्योग के लिए पुष्कर, दमिष्क/चैती गुलाब के लिए खमनौर (राजसमंद) है तो बीड़ी उद्योग के लिए ब्यावर प्रसिद्ध है।
- सर्वाधिक शराब बनाने के कारण 'राजस्थान का स्कॉटलैण्ड' कहलाने वाला जिला अलवर है जबकि सर्वाधिक एल्कोहॉल गंगानगर से प्राप्त होता है।
- राज्य में सबसे अधिक ताँबे के बर्तन भीलवाड़ा में, बनते हैं तो सर्वाधिक पीतल के बर्तन जयपुर में बनते है।
- राजस्थान के राजसमंद जिले के कांकरौली नामक स्थान पर टायर-ट्यूब बनाने का कारखाना है।
- राज्य में बड़ी लाईन के वेगन बनाने का कारखाना-कोटा में है तो मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना अजमेर में है।
- रेल के डिब्बे बनाने के लिए प्रसिद्ध रही सिमको वैगन फैक्ट्री जो वर्तमान में बंद है, राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है।
- जापानी कम्पनी होण्डा द्वारा अलवर जिले के खुशखेड़ा रीको औद्योगिक क्षेत्र में मोटर साइकिल स्कूटर कारखाने की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- देश का प्रथम ट्रांसपोर्ट हब राजस्थान के राजसमंद जिले के रेलमगरा में खुलेगा जहाँ वाहन व चालकों से से जुड़ी हर समस्या का समाधान होगा।
- **जोधपुर** में **ग्वारगम, हैण्डीक्राफ्ट** तथा अन्य विशिष्ट उत्पादों के विकास के लिए एक उच्च श्रेणी के अनुसंधान विकास केन्द्र की स्थापना जोधपुर (बोरानाड़) में की गई।
- भरतपुर के बाद भीलवाड़ा प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला होगा, जहाँ रेल कोच फैक्ट्री लगेगी।
- राज्य में प्लास्टिक उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु 'सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी' (सीपेट) चेन्नई द्वारा सीतापुरा (जयपुर) में स्थापित की गई।
- 'टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' जयपुर में बनाया गया है।
- देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क शाहगढ़ (जैसलमेर) में स्थापित किया जा रहा है।
- केन्द्र सरकार द्वारा 'कपड़ा निर्यातक शहर' और 'पावरलूम मेगा कलस्टर शहर' का दर्जा भीलवाड़ा को दिया गया है।
- सेल द्वारा राज्य में स्टील प्लांट भीलवाड़ा में लगाया जायेगा।
- पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स की स्थापना बाड़मेर में हो रही है।
- 'टेक्सटाइल पार्क' एवं 'टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' भीलवाड़ा में है।
- राजस्थान में कम्प्यूटर चलित गलीचा डिजाइन केन्द्र की स्थापना जयपुर में की जा रही है।
- भारत में प्रमुख उद्योग जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स (GEW) की तालाबंदी 2000 को हुई थी, जिसे 10 वर्ष पश्चात् 22 अप्रैल, 2010 को खोल दिया है।
- राज्य में फूड प्रोसेसिंग की वर्ल्ड क्लास लैब की स्थापना जयपुर में की जा रही है।
- सीतापुरा (जयपुर) में सेटेलाइट अर्थ स्टेशन पार्क व जोधपुर में साइबर पार्क स्थापित किया जा रहा है।
- जनजाति जिले में औद्योगिक विकास के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना-2010 शुरू की गई है-बाँसवाड़ा, डूंगरपुर व सिरोही में।
- राजस्थान में सीमेंट हब निम्बाहेड़ा (चित्तौड़) बनेगा।
- राजस्थान में DRDO द्वारा सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल-ब्रह्मोस का निर्माण पिलानी (झुंझुनूं) होगा।
- बहुराष्ट्रीय कम्पनी वावासी 45 हजार करोड़ का अपना सिलिकॉन और कम्प्यूटर चिप्स बनाने का प्लांट बीकानेर में लगा रही है।
- वरूण इंडस्ट्रीज मुम्बई द्वारा राज्य में स्टील प्लांट रोहट (पाली) लगाया जा रहा है।
- निप्पोन (थाइलैण्ड) की सियाम निप्पोन माजराकाठा (नीमराना) में 190 करोड़ निवेश कर वाहन उद्योग में उपयोगी स्टील ट्यूब कंपोनेंट का उत्पादन करेगी।
- भारत में औद्योगिक नगरी कानपुर है, तो राजस्थान में औद्योगिक नगरी कोटा है।
- वर्तमान में राज्य में 34 जिला उद्योग केन्द्र व 7 उपकेन्द्र (ब्यावर, फालना, आबू रोड़, बालोतरा, किशनगढ़, फलौदी व मकराना) कार्यरत है।

उद्योग प्रोत्साहन के लिए नीतियाँ

- **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना**-8 अक्टूबर, 2014-इस योजना प्रोत्साहन एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु राज्य सरकार की मंत्रीमण्डल की बैठक 8 अक्टूबर, 2014 को इस योजना का अनुमोदन किया। इस योजना की अवधि 2014 से 31 मार्च, 2019 तक रहेगी।
- **Vision-2020 :** हमारी सरकार द्वारा राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की कल्पना। कौशल विकास, ई-गवर्नेंस, अक्षय योजना, जल विकास, सहकारी क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र में किये गये कार्यों को राष्ट्रीय लेवल पर प्रस्तुत करने के लिए विजन-2020 को साकार करने के लिए।
- **मुख्यमंत्री सलाहकार परियोजना**-29 मई, 2014 को मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद् का गठन किया गया। राज्य के सतत्, संतुलित और तवरित विकास के लिए राज्य सरकार ने मार्च, 2014 में गठित राज्य आयोजना बोर्ड को भंग करके उसके स्थान पर मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद् का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगडिया होंगे।

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008**- उद्योग मंत्रालय द्वारा 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार एवं खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड व खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग द्वारा संचालित ग्रामीण सृजन कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नवीन योजना वर्ष 2008-09 में प्रारम्भ की गई।
- **मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना 2013**- मुख्यमंत्री द्वारा 2010-11 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई। इस योजना को 2010 में प्रारम्भ करना था, लेकिन मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना 2010 में प्रारम्भ की गई।
- **भामाशाह रोजगार सृजन योजना**-सुराज संकल्प 2013 में राज्य सरकार ने बेरोजगार युवक, महिलाओं, ST, SC के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकों से कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सुराज संकल्प 2013 के बिन्दुओं में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ब्याज अनुदान पर आधारित इस योजना का प्रारमी किया। योजना की अवधि 13 दिसम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक। राजस्थान सरकार की भामाशाह योजना को केन्द्र सरकार की मुद्रा योजना में सम्मिलित किया गया।

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015

- सीतापुरा (जयपुर) स्थित जयुपर एग्जीबिशन एण्ड कान्वेंशन सेन्टर में 19-20 नवम्बर, 2015 को रिसर्जेंट पार्टनरशिप समिट - 2015 का आयोजन किया गया।
- इस समिट के दौरान राजस्थान सरकार ने 20 नवम्बर, 2015 को रू 3.3 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित हेतु 295 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये।
- कार्यान्वित परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा।

सहमति पत्र (एमओयू) : एक नजर में

- इस समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य में लगभग 2,39,694 लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- ऊर्जा क्षेत्र में रू 1.9 लाख करोड़ के कुल 9 सहमति पत्रों (एमआयू) पर हस्ताक्षर हुए।
- पेट्रोलियम और खान के क्षेत्र में रू 77.657 करोड़ के कुल 25 सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- सड़क एवं राजमार्ग के क्षेत्र में रू 10,000 करोड़ के एमओयू हुए।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रू 17038 करोड़ तथा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रू 11760 करोड़ के एमओयू हुए।
- पर्यटन के क्षेत्र में रू 5783 करोड़ के एमओयू चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में रू 4752 करोड़ के एमओयू, कृषि क्षेत्र में रू 2402 करोड़ के एमओयू और शिक्षा के क्षेत्र में रू 1807 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
- रिसजेंट राजस्थान के तहत हुए कुल निवेश में से 83.38 प्रतिशत निवेश केवल ऊर्जा और खनन में आया हैं।
- ऊर्जा में (अधिकांशत: सोलर एनर्जी) 190 लाख करोड़ और 77.657 हजार करोड़ का निवेश खनन में आया है। अर्थात् कुल निवेश में से 2,67,657 करोड़ का निवेश इन दोनों में हैं।

निवेश (क्षेत्रवार एमओयू)

क्षेत्र	एमओयू संख्या	निवेश (रू करोड़ में)	रोजगार सृजन
कृषि	10	2402	5317
शिक्षा	8	1807	12010
ऊर्जा	9	190000	-
इन्फ्रास्ट्रक्चर	35	17038	46975
मैन्यूफैक्चरिंग	40	11760	56698
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	36	4752	81605
पेट्रोलियम व खान	25	77657	18472
सड़क एवं उच्च मार्ग	1 4(मंजूरी)	10000 25446	
कौशल विकास	9		
पर्यटन	122	5783	18617
कुल	**295**	**321199**	**239694**

- केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारमण ने राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ **डिजायन (अहमदाबाद) की एक शाखा राज्य में खोलने की घोषणा की।**
- केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए आईपीडीएस योजना के तहत रू 325 करोड़ देने की घोषणा की।
- केन्द्रीय रसायन, उर्वरक और फार्मा मंत्री अंनत कुमार ने राज्य में रू 10,000 करोड़ मूल्य के प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की। इनमें-
- झालावाड़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एण्ड रिसर्च (नाइपर)
- सेंटल इंस्ट्रीयूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट) के जयपुर केन्द्र को अपग्रेड करने के लिए रू 100 करोड़ का निवेश।
- चित्तौड़गढ़ में रू 100 करोड़ के निवेश से सिंगल सुपर फॉस्फेट का कारखाना।
- कोटा में 5500 करोड़ का यूरिया क्षेत्र में निवेश किया जायेगा।
- भिवाड़ी (अलवर) क्षेत्र में रू 1000 करोड़ की लागत से **प्लास्टिक पार्क** तथा 100 करोड़ के निवेश से **मेडिकल डिवाइसेज पार्क।**
- आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमेन कुमार मंगलम बिड़ला ने गोटन और नवलगढ़ में सीमेंट उद्योग लगाने की घोषणा की है, जिस पर रू 7000 करोड़ का निवेश किया जायेगा। इसके अलावा मोबाइल क्षेत्र और सौर ऊर्जा सहित प्रदेश रू 11000 करोड़ निवेश की घोषणा
- अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में रू 60000 करोड़ के निवेश योजना की घोषणा की।
- हीरो मोटाकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने जयपुर में **'राज्य कला अनुसंधान एवं विकास केन्द्र'** के स्थापना करने की घोषणा की।
- सिंगापुर के गृह व कानूनी मंत्री शणमुगम ने सिंगापुर एयरलाइंस की ओर से जयपुर से सिंगापुर के मध्य शीध्र ही विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की।

विशेष औद्योगिक पार्क

1. जेम्स एण्ड ज्वैलरी – निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क, सीतापुरा (जयपुर)।
2. हौजरी – चोपन्की (भिवाड़ी) व सीतापुरा (जयपुर)।
3. ऑटो सहायक पार्ट्स – घटल (भिवाड़ी) व सीतापुरा (जयपुर)।
4. ऑटोमोबाइल कॉम्पलेक्स – बाड़मेर
5. सिरेमिक्स – खारा (बीकानेर)
6. इलेक्ट्रोनिक्स – इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर टेक्नॉलाजी पार्क कूकस (आमेर, जयपुर)।

नोट : यहाँ स्वीडन के सहयोग से इलेक्ट्रोनिक्स स्विचिंग सिस्टम लगाया गया है।

7. सॉफ्टवेयर टैक्टनालॉजी पार्क – कनकपुरा, जयपुर।
8. इंटीग्रेड टेक्सटाइल पार्क – रीको द्वारा किशनगढ़ (अजमेर), सोनीयान (चित्तोड़गढ़), बालोतरा (बाड़मेर), मण्डा-भिण्डा (कालाडेरा), जयपुर, के पास नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
9. सूचना टेक्नालॉजी – सीतापुरा (जयपुर) (यहाँ एक अर्थ स्टेशन व सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है।
10. कृषि उद्योग क्षेत्र – बीकानेर व जैसलमेर में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में।
11. चमड़ा – मानपुरा-माचेड़ी (चन्दवाजी, जयपुर), सीतापुर (जयपुर), भिवाड़ी (अलवर)।

नोट : मानपुरा माचेड़ी में कॉमन एफ्ल्यूमेंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है।

12. ऊन – वूल कॉम्प्लेक्स, गोहना (ब्यावर, अजमेर) व जैसलमेर।
13. दस्तकारी – शिल्पग्राम-जोधपुर (पाल-शिल्प ग्राम) व जैसलमेर।

नोट : जयपुर में राजसीको द्वारा हैण्डीक्राफ्ट कम टूरिज्म कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जायेगा।

14. पुष्प पार्क – खुशखेड़ा (अलवर)
15. लघु खनिज कॉम्प्लेक्स – करौली, दोहिन्डा (राजसमंद) व मित्रपुरा (दौसा), सवाई माधोपुर।

सूती वस्त्र उद्योग

- कृषि आधारित देश का सबसे बड़ा उद्योग है।
- देश में प्रथम सूती मिल की स्थापना कलकता में घूसरी नाम स्थान पर 1818 ई.।
- महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा गुजरात सूती वस्त्र का प्रमुख केन्द्र।
- यह राजस्थान का परम्परागत एवं प्राचीन उद्योग।
- यह उद्योग राज्य में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- विश्व में चीन सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान पर, भारत का तीसरा स्थान
- राज्य में प्रथम सूची वस्त्र मिल की स्थापना 'दी कृष्णा मिल लि. 1889' में ब्यावर (अजमेर) में निजी क्षेत्र में (सेठ दामोदर दास द्वारा)
- मेवाड़ टैक्स टाइल्स मिल लिमिटेड - 1938 (भीलवाड़ा)।
- महाराजा उम्मेदसिंह मिल्स लिमिटेड - 1942 (पाली)।
- सार्दल टैक्स टाईल्स लिमिटेड - 1946 (श्रीगंगानगर)।
- कोटा टैक्स टाइल्स मिल्स लिमिटेड - 1956 (कोटा)।
- राजस्थान स्पिनिंग एवं जिंनिग मिल्स - 1960 (खारीग्राम भीलवाड़ा)।

सार्वजनिक मिलें

- एडवर्ड मिल्स – ब्यावर (अजमेर)
- महालक्ष्मी मिल्स – ब्यावर (अजमेर)
- विजय कॉटन मिल्स – विजयनगर (अजमेर)

सहकारी मिलें

राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड - गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) स्थापना - 1965
श्रीगंगानगर सहाकरी कताई मिल्स लिमिटेड- स्थापना 1981
श्रीगंगापुर (भीलवाड़ा)

नोट- 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों कताई मिलों एवं गुलाबपुरा की सहकारी कताई को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एण्ड जिनिंग मिल संघ लिमिटेड की स्थापना की गई वर्तमान में बंद।

- राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स - महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स (पाली)
- कार्यशील करघों की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी मि. कृष्णा मिल्स -ब्यावर (अजमेर)
- टेक्सटाइल पार्क - भीलवाड़ा
- पावरलूम उद्योग में कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर-भीलवाड़ा

चीनी उद्योग

- देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग
- बूँदी, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन।
- रूस, ब्राजील, क्यूबा के बाद भारत चौथा बड़ा चीनी उत्पादक
- भारत विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक
- उत्तर प्रदेश तथा बिहारी चीनी उद्योग की दृष्टि से प्रमुख राज्य

चीनी मिले

दी. मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेडः-

- भोपाल सागर (चित्तौड़)
- स्थापना-1932
- निजी क्षेत्र में स्थापित राज्य की प्रथम मिल

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड-

- श्रीगंगानगर
- स्थापना - 1956
- सार्वजनिक क्षेत्र में
- इसके अधीन राशन तथा स्पिरित बनाने के कारखाने स्थापित
- 1937 को बीकानेर इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन नाम से स्थापित
- 1 नवम्बर 1956 से सर्वाजनिक क्षेत्र में

नोट- यहां चुकन्दर से चीनी बनाने की योजना 1968 में आरम्भ की गई लेकिन हाल में सरकार ने इसे अनार्थिक इकाई मानते हुए इसे बन्द करने का निर्णय लिया।

केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड-

- केशोराय पाटन (बूँदी)
- स्थापना - 1965
- स्हकारी क्षेत्र में।

1976 ई. उदयपुर में शुगर मिल की स्थापना की गई।

सीमेंट उद्योग

- सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान।
- देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 15.58 प्रतिशत राजस्थान में।
- चीन के बाद विश्व में भारत दूसरा बड़ा उत्पादक देश।
- भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना की स्थापना 1904 ई. मद्रास में।
- राज्य में सर्वप्रथम सीमेंट कारखानें की स्थापना स्लीक निकसंन कंपनी द्वारा लाखेरी (बूँदी) में 1917 ई. में की गयी।

कारखाने

जयपुर उद्योग लि. (बाबरा) सवाई माधोपुर
- स्थापना 1953 में की गयी।
- त्रिभुवन छाप सीमेंट
- एशिया सबसे बड़ा कारखाना जो वर्तमान में बंद।

बिड़ला जूट - चित्तौड़
- स्थापना 10 मई, 1967
- चेतक छाप सीमेंट हेतु प्रसिद्ध।

हिन्दुस्तान शुगर - उदयपुर
- जे.के. सीमेंट - निम्बाहेड़ा (चित्तौड़)
- स्थापना - 1974
- उत्पादन की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा।

मंगलम सीमेंट - मोदक (कोटा)

श्री सीमेंट - ब्यावर (अजमेर)
- 2005/2008 में ''गोल्डन पीकॉक अवार्ड'' दिया गया।
- भारत की सबसे बड़ी सीमेंन्ट कंपनी।
- स्थापना- 1905।

बागड़ सीमेंट- रास बाबरा क्षेत्र (पाली)।

अंबूजा सीमेंट- रास बाबरा क्षेत्र (पाली)।

श्रीराम सीमेंट-
- श्रीराम नगर (कोट)
- सबसे कम उत्पादन क्षमता।
- पोर्टलैण्ड सीमेंट - केरपुरा व दयालपुरा गांव (पाली)
- त्रिगुल छाप सीमेंट - सवाई माधोपुर।

सQद सीमेंट-
- जे.के. सीमेंट -गोटन (नागौर)
- बिड़ला व्हाइट सीमेंट - भोपालगढ़ (जोधपुर)
- इण्डियन रेयॉन इण्डिस्ट्रीज लि. - खारिया खंगार (जोधपुर)।
- राजस्थान का सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना खारिया(जोधपुर) में ही स्थित है।
- नोट - तुलसीराम की ढ़ाणी, खीयां खिवंसर (जैसलमेर) में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोर के विपुल भण्डार मिले।
- जैसलमेर जिले के सोनु क्षेत्र में RSMML तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से सीमेंट कारखाना स्थापित।
- झुंझुनू की नवलगढ़ तहसील में खिरोड़ी तथा परसरामपुरा गांवों में निजी क्षेत्र में सीमेंट कारखाने प्रस्तावित।

नमक उद्योग

- भारत का विश्व में चौथ स्थान।
- देश का लगभग 12 प्रतिशत नमक का उत्पादन राज्य में।
- झीलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान।
- राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के कारखाने-सांभर, डीडवाना, पचपदरा।
- सांभर झील देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक स्त्रोत, जो कुल उत्पादन का 8.7 प्रतिशत है।
- सांभर झील से नमक उत्पादन का कार्य सांभर सॉल्ट्स लि. द्वारा किया जा रहा है। जो केन्द्र सरकार का उपक्रम है।
- राज्य में कुल नमक उत्पादन का 70 प्रतिशत भाग सार्वजनिक क्षेत्र में।
- हीरागढ़ व साम्बरा (पचपदरा) नमक उत्पादक क्षेत्र।
- डीडवाना में **खरवाल जाति** के लोगों द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन में लगी निजी संस्थाएं स्थानीय भाषा में **देवल** कहलाती है।
- लवण निर्माताओं को तकनीकि ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु मॉडल सॉल्ट फॉर्म, नावां (नागौर) में स्थापित।
- 12 जनवरी 2002 अमेरिका व जर्मनी के सहयोग से।
- साबू सोडियम परियोजना गोविन्द ग्राम (नावां, नागौर) में चलाई जा रही है जो उत्तरी भारत की सबसे बड़ी।

पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड
- स्थापना - 1960
- प्रतिवर्ष 6 लाख क्विंटल उत्पादन
- 10.10.2008 को निजीकरण

सांभर सॉल्ट लिमिटेड
- सांभर (जयपुर)
- स्थापना - 30 सितम्बर 1994
- केन्द्रीय सरकार का उपक्रम।

राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स
- डीडवाना (नागौर)
- स्थापना - 1964। 10.10.2008 को निजीकरण।
- सोडियम सल्फेट, सल्फाइट के कारखाने।

कांच उद्योग

- कांच उत्पादन हेतु बालु मिट्टी, सिलिका, सोडियम सल्फेट व शीशे की आवश्यकता।
- सिलिका उत्पादन में राजस्थान हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पर।

हाइटैक प्रिसिजन ग्लास Qक्ट्री
- धौलपुर।
- यह श्री गंगानगर शुगर मिल की सहायक कंपनी है।
- यहाँ शराब की बोंतलों का निर्माण होता है।

धौलपुर ग्लास वर्क्स
- धौलपुर
- निजी क्षेत्र में स्थापित।

सेमकोर ग्लास इण्डस्ट्रीज-
- कोटा
- टी.वी. पिक्चर ट्यूब बनाने हेतु।
- सिरेमिक पार्क - बीकानेर।
- कांच उद्योग का केन्द्रीयकरण सर्वाधिक धौलपुर जिले में है।

ऊन उद्योग
- राजस्थान सर्वाधिक ऊन उत्पादक करने वाला राज्य।
- देश के कुल उत्पादन का राज्य में उत्पादन 45 प्रतिशत होता है।
- सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर जिले में होता है।
- भीलवाड़ा में ऊन उद्योग से संबंधी विधायन गृह की स्थापना की गयी।
- अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड ने अक्टूबर 1992 में बीकानेर में गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

- बीकानेर, जोधपुर ब्यावर ऊनी वस्त्र के प्रमुख उत्पादक केन्द्र।
- राज्य में ऊन की प्रमुख मण्डिया बीकानेर, पाली, केकड़ी औसियां, ब्यावर में।

रासायनिक उद्योग

- 1964 ई. में स्थापित राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कारखाना डीडवाना में सोडियम सल्फेट का उत्पादन करती है। जिसका उपयोग कांच, सूती रेशमी व ऊनी कपड़ों को बनाने में किया जाता है।

श्री राम Qर्टीलाजर
- कोटा
- रासायनिक खाद्य के उत्पादन हेतु।
- निजी क्षेत्र में।

जिंक स्मेल्टर कारखाना
- देबारी (उदयपुर)
- रासायनिक खाद उत्पादन हेतु।

चम्बल फटीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज
- गड़ेपान (कोटा)।
- गैस आधारित कारखाना।
- निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा कारखाना।
- इसका संचालन कुमार मंगलम बिड़ला द्वारा किया जाता है।

फॉस्फेट एण्ड फर्टीलाइजर्स - उदयपुर ।
- मोदी एल्केलाइज एण्ड केमिकल लि.-अलवर

उद्योगों से संबंधित विशेष

कैप्टन मीटर कंपनी कारखाना -
- जयपुर व पाली।
- पानी के मीटर बनाये जाते है।

जयपुर मेटल-
- जयपुर।
- बिजली के मीटर बनाये जाते है।

मान इण्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन
- जयपुर
- लोहे के टॉवर तथा इमारती खिड़की बनाने के लिए।

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड-
- जयपुर
- टेलीविजन सेट्स बनाने हेतु।

टायर ट्यूब कारखाना- कांकरोली (राजसमंद)
आमेर वनस्पति घी कारखाना - झोटवाड़ा (जयपुर)
केसरी व वनस्पति घी कारखाना - निवाई (टोंक)
महाराजा वनस्पति घी कारखाना - जयपुर।
सर्वाधिक औधोगिक इकाईयां - जयपुर।
सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाईयां - अलवर
बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाईयां - भिवाड़ी (अलवर)
न्यूनतम औद्योगिक इकाईयां - जैसलमेर।
राज्य में बड़ी लाईन के वैगन बनाने का कारखाना - कोटा।
मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना - अजमेर।
कम्प्यूटर ऐडेड डिजाइन सेंटर - जयपुर।
हैण्डलूम डिजाइन डवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेंटर-नागौर।
हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान - सांगानेर (जयपुर)।
प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी - जयपुर।

राजस्थान में भारत सरकार के उपक्रम

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड - देबारी (उदयपुर)
- प्रधान कार्यालय - उदयपुर।
- स्थापना - 10 जनवरी, 1966।
- जस्ता गलाने का संयंत्र।
- जावर, दरीबा, से कच्चा जस्ता निकालकर देबारी स्थित परिशोधन संस्थान में परिशोधन।

हिन्दुस्तान लिमिटेड - खेतड़ी (झुंझुनू)
- स्थापना - 1967
- अमेरिका की वैस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से तांबा शोधन संयंत्र।
- खेतड़ी में ताबें के अलावा ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट द्वारा खाद तैयार की जाती है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स-अजमेर
- स्थापना- 1967
- चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से।
- प्रीसीजन ग्राइडिंग मशीनों के निर्माण करने के लिए 1967 में दी मशीन टूल फैक्ट्री की अजमेर में स्थापना की जिसका नाम बदलकर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कर दिया।

इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड - कोटा
- स्थापना -मार्च, 1964।
- प्रधान कार्यालय - जयपुर।
- इसकी एक इकाई पालघाट (केरल) में।
- राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इन्ट्रूमेन्ट्स लि. जयपुर इसकी एक सहायक कंपनी है। जो रीको के साथ संयुक्त क्षेत्र में 1982-83 में स्थापित।
- इसमें तरल पदार्थों की जांच के उपकरण एवं दूध की जांच हेतु लैक्टोमीटर बनाये जाते है।

सांभर साल्ट लि. - सांभर (जयपुर)
- स्थापना - 30 दिसम्बर 1964।
- इसमें 60 प्रतिशत अंश हिन्दुस्तान सॉल्ट्स का तथा 40 प्रतिशत अंश राजस्थान सरकार का।

मॉर्डन बेकरीज - जयपुर
- 1965 में स्थापित।
- विश्वकर्मा औधोगिक क्षेत्र में।

राजस्थान ड्रग्स एण्ड Qार्मा स्यूटिकल्स लि. - जयपुर।
- केन्द्र सरकार की इस कंपनी की स्थापना 1978 में रीको की साझेदारी से जयपुर में की गई। यह वर्तमान में बंद है।

राजस्थान में परिवहन

सड़क परिवहन

- 31 मार्च, 1951 को राज्य में सड़कों की लम्बाई 17339 किमी. थी
- राज्य में मार्च, 2015 को सड़को की कुल लम्बाई 2,08 341. 81 किमी थी। राष्ट्रीय औसत 148 किमी के विरूद्ध राज्य में प्रति 100 वर्ग मीटर पर 60.55 किमी का सड़क घनत्व है। **Source: आर्थिक समीक्षा** 2015-16
- राजस्थान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) की सर्वाधिक लम्बाई वाला राज्य बन गया है। सितम्बर, 2015 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की वेबसाइट के अनुसार भारत में 96,260.48 किमी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लम्बाई वाले राज्य क्रमशः राजस्थान (7886.20 Km), उत्तरप्रदेश (7863Km) एवं महाराष्ट्र (7047.79 Km) है।
- राज्य में परिवहन सेवाओं को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए राज्य को परिवहन के दृष्टिगत 11 संभागों (R.T.O) एवं 52 परिवहन जिलों (D.T.O) में विभाजित किया गया है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य में लम्बाई
  -7886.20 किमी. (दिसम्बर, 2015 तक)
- राजस्थान में सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग
  - एन.एच. 71 बी (5 किमी.)
- राजस्थान में सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग
  -एन.एच. 15 (906 किमी.)
- न्यूनतम सड़कों वाला जिला **- धौलपुर**
- सर्वाधिक लम्बी सड़कों वाला जिला **- बाड़मेर**
- सड़कों से जुड़े न्यूनतम गॉवों वाला जिला **- सिरोही**
- सड़कों का न्यूनतम घनत्व वाला जिला **- जैसलमेर**
- सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला - राजसमन्द
- राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लम्बाई वाला जिला
  -उदयपुर
- राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई वाला जिला
  -हनुमानगढ़
- राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे
  -जयपुर से किशनगढ़
- राजस्थान में सड़क घनत्व - **72.64 प्रति 100 वर्ग किमी.**
- राजस्थान में राज्य उच्च मार्ग (S.H.)
  87- (लम्बाई-12089.55 किमी.)
- राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या **-29/31***
- सबसे लम्बा राज्य उच्च मार्ग (S.H.)
  -एस. एच. 1 (444 किमी.
  * राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार
- सड़कों से जुड़े पंचायत मुख्यालय - राजसमंद।
- राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग - NH-8 (677 किमी)।
- सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वाला जिला - अजमेर (8,14,79,79A,89), जयपुर (8,11,11A,11C,12)।
- सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-11-(6 जिले) NH-15, (7 जिले)NH, - 76 (7 जिले)।
- कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं - झुंझूनूँ।
- राज्य उच्च मार्ग (State Highways)- 86 (झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपूर, करौली, भरतपुर)
- सबसे बड़ा राज्य उच्च मार्ग -SH-1 -(झालावाड़ से भरतपुर लम्बाई -432 किमी.)
- सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग SH-9B -(सुकेत-रामग्रज मंडी, कोटा, लम्बाई-11किमी)
- केवल राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-11A, 11 A A, 11 B, 79, 79 A, 89, 90, 112, 114, 116 (10)
- दूसरा सबसे लम्बा राज्य उच्च मार्ग- SH -7 (किशनगढ़ (अजमेर)-सांगरिया (हनुमानगढ़)।
- दूसरा सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग- 19B (मांगरोल-राजपुरा-बारा)-16किमी.।
- राजस्थान में परिवहन सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं परिवीक्षण हेतु राज्य को परिवहन की दृष्टि से 13 संभागों एवं 52 जिलों में विभाजित किया गया है। दो प्रमुख कर संग्रह केन्द्रों शाहजहॉपुर (अलवर) एवं रतनपुर (डूँगरपुर) में भी जिला परिवहन अधिकारी के पद सृजित है।

क्र.	संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग में आने वाले जिले	लंबाई
1.	3	आगरा-धौलपुर-मुम्बई (राज्य का दूसरा सबसे छोटा	धौलपुर	29
2.	8	दिल्ली-जयपुर-अजमेर-उदयपुर-अहमदाबाद (राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य को दो भागें में विभाजित करते है।	अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर (न्यूनतम, जयपुर (सर्वाधिक)	677
3.	11	आगरा-भरतपुर-दौसा- जयपुर-सीकर- बीकानेर	भरतपुर (न्यूनतम), दौसा, जयपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू (सर्वाधिक)	524
4.	11A	दौसा-मनोहरपुर वाया घरवाड़ी (राष्ट्रीय राजमार्ग 11 को NH.8 से जोड़ता है।)	दौसा, जयपुर (सर्वाधिक)	62
5.	11AA	दौसा-मनोहरपुर वाया धरवाड़ी (राष्ट्रीय राजमार्ग 11 को NH-8 से जोड़ता है।)	दौसा (सर्वाधिक), टोंक	83
6.	11 B	लालसोट-गंगापुर-करौली-धौलपुर	दौसा (न्यूनतम), करौली,धौलपुर	187
7.	11C	चंदवाजी-जयपुर	जयपुर	54
8.	12	जयपुर-टोंक-बूंदी-कोटा-झालावाड़-इकलेरा-जबलपुर	जयपुर, टोंक (सर्वाधिक) भीलवाड़ा, (न्यूनतम),	412

		(मध्यप्रदेश)	बूंदी, कोटा, झालावाड़	
9.	14	ब्यावर-पाली-सिरोही-आबूरोड़-कांडला	अजमेर, पाली (सर्वाधिक), सिरोही, (न्यूनतम)	306
10	15	पठानकोट-श्रीगंगानगर-बीकानेर-जैसलमेर-बाड़मेर-समख्याली (गुजरात) (सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग)	श्रीगंगानगर, बीकानेर,जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर,हनुमानगढ़ (न्यूनतम)	875
11	65	अम्बाला(हरियाणा)-चूरू-फतेहपुर-नागौर-जोधपुर-पाली	सीकर, चूरू, जोधपुर, नागौर (सर्वाधिक), पाली,(न्यूनतम)	495
12	71B	रेवाड़ी-अलवर-धारूहेड़ा (हरियाणा) (सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, वर्तमान नाम 919NH कर दिया गया)	अलवर	5
13	76	पिण्डवाड़ा-उदयपुर-चितौड़गढ़-कोटा-बारां-शिवपुरी (राज्य का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग को अन्य राज्य से अलग करता है।) वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 कर दिया गया है।	सिरोही (न्यूनतम, उदयपुर,चितौड़, भीलवाड़,बूंदी, कोटा, बारां, (सर्वाधिक)	578
14	79	अजमेर-नसीराबाद- निजौलिया-चितौड़गढ़	अजमेर (न्यूनतम), भीलवाडा (सर्वाधिक) चितौड़	221
15	79A	किशनगढ़-नसीराबाद-अजमेर-(राज्य का तीसरा सबसे छोटा, पूर्ण राजस्थान में गुजरने वाला सबसे छोटा)	अजमेर	38
16	89	अजमेर-नागौर-बीकानेर	अजमेर (न्यूनतम), बीकानेर, नागौर (सर्वाधिक)	278
17	90	बरां-इकलेरा (राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को 76 से जोड़ता है।)	बारां (सर्वाधिक), झालावाड़	94
18	112	बाड़मेर-बालोतरा-जोधपुर बिलाड़ा पूर्णतः राजस्थान में गुजरने वाला सबसे लंबा, NH14 को 15 से जोड़ता है।	बाड़मेर (सर्वाधिक), जोधपुर, पाली (न्यूनतम)	94
19	113	निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़- बांसवाड़ा-जहलोड- दाहोड	बांसवाड़ा (सर्वाधिक), प्रतापगढ़,चितौड़ (न्यूनतम)	225
20	114	जोधपुर-पोकरण	जोधपुर (सर्वाधिक), जैसलमेर	177
21	116	टोंक-सवाई माधोपुर	टोंक, सवाई माधोपुर (सर्वाधिक)	78

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहें

क्र.सं.	स्थान	राष्ट्रीय राजमार्ग (N.H.)
1	फतेहपुर (सीकर)	11 एवं 69
2	ब्यावर	8 एवं 158
3	नाथद्वारा (राजसमंद)	8 एवं 162
4	उदयपुर	8 एवं 76
5	दौसा	11 एवं 11A
6	कोटा	12 एवं 76
7	पाली	14,65 एवं 165 Ext.
8	मेड़ता (नागौर)	89 एवं 65 A
9	लांबिया (पाली)	65 A एवं 158
10	रायपुर (पाली)	14 एवं 927 A
11	चित्तौड़गढ़	76 एवं 79
12	सोम (उदयपुर)	76 A एवं 927 A
13	भीलवाड़ा	79 एवं 76 B
14	नागौर	65 एवं 89
15	जैतारण (पाली)	65 A एवं 112
16	बॉसवाड़ा	113 एवं 927 A
17	खैरवाड़ा (उदयपुर)	8 एवं 927 A

मुख्यमंत्री सड़क योजना :-

- प्रारम्भ - 7 अक्टूबर, 2005
- राज्य में प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु 1000 किमी.
- राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क (मॉडल रोड़) का विकास

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :-

- प्रारम्भ 25 दिसम्बर 2000
- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत सड़कों का विकास व निर्माण
- इस योजना में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार सामान्य आबादी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी के गांवों को तथा मरू व जनजातीय क्षेत्र में 250 तक के आबादी के गांवों को।
- 1994 में राज्य सरकार द्वारा देश में सर्वप्रथम सड़क नीति घोषित की गई।
- 2002 नवीन सड़क नीति घोषित।
- उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई वाला राज्य।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना -

- यह परियोजना 1990-2000 में संचालित की गई।
- उद्देश्य - 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 तथा 6 लेन में बदलना।
- वित्तीय सहायता विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जापान।

इस परियोजना में निम्न कार्य संचलित किये जा रहे हैं-

1- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (स्वर्णिम चतुर्भुज) (प्रथम चरण): इसके अंतर्गत चारों महानगरों दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता को 4 व 6 लेन से जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत 8,79,79 तथा 76 को शामिल। जिसकी कुल लम्बाई 694 किमी। अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूँगरपुर

2- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (पूर्व-पश्चिम गलियार) (द्वितीय चरण):- यह परियोजना सिलचर (आसाम) को पोरबंदर (गुजरात) को आपस में जोड़ने से संबंधित। इसमें राजस्थान के अंतर्गत NH-14,76 को शामिल। इस परियोजना में राज्य में कुल लम्बाई 528 किमी। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूँदी, कोटा, बारां शामिल।

3- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (उत्तर-दक्षिणी गलियारा) (तृतीय चरण):- यह योजना कश्मीर से कन्याकुमारी को आपस में जोड़ने से संबंधित। इसमें राजस्थान के NH 3 को शामिल किया गया है जिसकी लम्बाई 28 किमी है। यह केवल धौलपुर से गुजरता है।

रेल परिवहन

- विश्व में पहली रेल सेवा की शुरूआत 1826 में इंग्लैण्ड में।
- भारत में रेल सेवा का प्रारम्भ 16 अप्रैल, 1853 को
- (बोरीबंदर-मुम्बई से थाने के बीच 33.81 किमी.)
- यह रेल ग्रेट- इंडियन पेनिस्यूलर रेलवे कम्पनी से स्थापित की।
- भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी है तथा विश्व की दूसरी बड़ी हैं।
- राजस्थान में तत्कालीन जयपुर रियासत के बांदीकुई (वर्तमान दौसा जिले में) आगरा फोर्ट (यू.पी) के मध्य 20 अप्रैल, 1874 ई. में सर्वप्रथम रेल चली।
- राज्य की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण वर्ष 1873 में आगरा-भरतपुर के मध्य हुआ।
- भारतीय रेलवे के 17 जोन (16 कोलकत्ता मेट्रो) एवं 67 मण्डलों में से चार जोन एवं आठ मण्डलों (जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, आगरा, झाँसी एवं दिल्ली) का कार्यक्षेत्र राजस्थान में पड़ता है।
- उत्तर-पश्चिमी रेलवे जोन की स्थापना जयपुर में 1 अक्टूबर, 2002 को की गई है। इस जोन के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर मंडल आते हैं।
- राज्य में रेलमार्गों की कुल लम्बाई 5871.65 किमी. है, इसमें 81.77 प्रतिशत ब्रॉडगेज, 16.75 प्रतिशत मीटरगेज एवं 1.48 प्रतिशत नैरोगेज रेलमार्ग सम्मिलित हैं।
- उत्तरप्रदेश के बाद राजस्थान देश में रेलमार्ग की सर्वाधिक लम्बाई वाला दूसरा राज्य है।
- राज्य के अधिकाशं रेलमार्ग उत्तर-पश्चिम रेलवे (NWR) के अंतर्गत आते हैं। उत्तर-पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयुपर है।
- राज्य में रेलमार्ग का घनत्व 17.16 किमी. प्रति हजार वर्ग किमी है।
- राज्य का नवीनतम रेलखण्ड (रेलमार्ग) अजमेर (मदार)-पुष्कर 23 जनवरी, 2012 को प्रारम्भ हो गया। इसकी कुल लम्बाई 24.27 किलोमीटर है।
- राजस्थान के बाँसवाड़ा एवं प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक, झालावाड़ एवं करौली कुल छः जिला मुख्यालय रेल सेवा से वंचित है।
- डूंगरपुर-बाँसवाड़ा-रतलाम रेलमार्ग (176 किमी.) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस रेलमार्ग के निर्माण हेतु भूमि एवं 50 प्रतिशत राशि राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रही है।
- आजादी से पूर्व जोधपुर तथा बीकानेर रियासतों ने सर्वप्रथम अपने निजी राजमार्ग स्थापित किये।
- फुलेरा (जयपुर) में एशिया का सबसे बड़ा मीटरगेज यार्ड स्थापित।
- राज्य में प्रथम मीटर गेज रेलवे लाईन 14 फरवरी, 1873ई. को प्रारम्भ की गई।
- रेल मार्ग की लम्बाई की दृष्टि से राज्य का देश में 12वां स्थान।
- 12 अक्टूबर को देश में प्रथम रेल बस मेड़ता रोड़ से मेड़ता सिटी के बीच चलाई गई।
- अजमेर की रेलवे वर्कशॉप भारत की एकमात्र वर्कशॉप जहाँ ईंजन बनते है।
- राजस्थान की एकमात्र नेरोगेज लाईन धौलपुर में है। जो 'बच्चा गाड़ी के नाम से लोकप्रिय है। रियासत काल में 1908 में प्रारम्भ हुई जो समरपुरा तक 72 किमी सफर तीन घंटे में इनमें कुल पांच डिब्बे।
- देश की पहली डबल स्टैक कैटेनर ट्रेन का शुभारंभ कनकपुरा (जयपुर) से पीपावाव पोर्ट (गुजरात) तक।
- राज्य में वर्तमान में एक जोन एवं पांच मंडल कार्यालय-
- **जोन - उत्तर-पश्चिमी रेलवे - जयपुर**
- **मण्डल - जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर,**
- **कोटा मण्डल- पश्चिमी मध्यजोन में हैं जिसका मुख्यालय-जबलपुर (मध्यप्रदेश)**
- **ब्रोडगेज** - 68.37 **प्रतिशत** - 1.67 **मीटर**
- मीटरगेज - 30.10 प्रतिशत - 1.00 मीटर
- नैरोगेज-1.53 प्रतिशत- 0.62 मीटर से 0.73 मीटर

भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केन्द्र :-

- पचपदरा (बाड़मेर)
- 180 किमी/घंटा से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण

सिमको वैगन Qक्ट्री :-

- प्रारम्भ - 31 जनवरी, 1957।
- भरतपुर की यह फैक्ट्री 8 साल बाद 9 अक्टूबर, 2008 को पुनः चालू।
- इसे टीडागढ़ वैगन्स लि. कंपनी ने पुनः प्रारम्भ
- 9 अक्टूबर 2000 बंद
- स्थापना - 1957 ई.। संचालन बिड़ला समूह द्वारा।

पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र :-

- उदयपुर, स्थापना 9 अक्टूबर, 1965
- यहाँ भारत का सबसे बड़ॉ मॉडल कक्ष स्थापित

रतलाम-बांसवाड़ा-डँगरपुर रेल्वे लाईन :-

- उद्घाटन - 3 जून 2011 यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बांसवाड़ा में।

थार एक्सप्रेसः-

मुनावाब (बाड़मेर) से खोखरापार, (मीरपुरखास, पाक) के बीच 18 फरवरी 2006 से रेल सेवा प्रारम्भ, अब जोधपुर से मुनावब तक की रेल को लिंक एक्सप्रेस तथा मुनाबाव से जीरापॉइन्ट तक की रेल को थार एक्सप्रेस।

वायु परिवहन

- राजस्थान में सर्वप्रथम 1921 में जोधपुर के महाराजा श्री उम्मेदसिंह ने फ्लाइंग क्लब खोला।
- वर्तमान में कुल आठ एयरपोर्ट तथा 18 हवाई पट्टियां है।
- बीकानेर, जोधपुर, सूरतगढ़, जैसलमेर एवं बाड़मेर एयरपोर्ट भारतीय वायु सेना के अधीन है।
- 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीय करण कर दिया गया।
- भारतीय संविधान में विमानपतन को संघ सूची का विषय बनाया गया।
- **प्रमुख हवाई अड्डे** -
  (A) सांगानेर एयरपोर्ट - जयपुर
  (B) डबोक एयरपोर्ट - उदयपुर
  (C) रातानाडा एयरपोर्ट - जोधपुर
  (D) कोटा एयरपोर्ट - कोटा
  (E) जैसलमेर एयरपोर्ट - जैसलमेर
  (F) नाल एयरपोर्ट - बीकानेर
- नाल (बीकानेर), सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) भूमिगत हवाई अड्डे।
- संगानेर एयरपोर्ट का 2005 में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया।
- जोधपुर तथा बीकानेर एयरपोर्ट सामारिक दृष्टि से महत्वूपर्ण।
- जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा जहाँ प्रशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध है।
- 29 दिसम्बर 2005 को सांगानेर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया तथा यह देश का 14 वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई बन गया।
- महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक देश के 16वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में प्रस्तापित।
- 20 दिसम्बर 2006 को राज्य में नागर विमानन निगम की स्थापना की गई।

निर्माण IAS

राजस्थान की मिट्टीयाँ

रेतीला या मरूस्थलीय मिट्टी :-

- इसे बलुई मिट्टी या बालू रेत भी कहते है।
- इस मिट्टी में मोटे कण तथा पानी ग्रहण करने की क्षमता कम होती है।
- लवण का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक होता है।
- राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पायी जाती है।
- सर्वाधिक विस्तार राज्य के पश्चिमी भाग में है।
- यह वायु द्वारा निक्षेपित मिट्टीयां से निर्मित होती है।
- इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मैंगनीज तथा तांबे की कमी होती है।
- इसमें कैल्सियम की अधिकता।
- इसका pH मान अधिक तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है।
- श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझूनू, नागौर पाली जिलों में मिलती है।

पर्वतीय मिट्टी -

- अरावली प्रदेश के नीचे के क्षेत्रों में पायी जाती है।
- मिट्टी का रंग लाल, पीला, भूरा।
- पहाड़ी ढलानों पर अधिक विस्तार है।
- इनमें कृषि नहीं की जा सकती, केवल जंगल पाये जाते है।
- सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर व अलवर जिलों में अधिकता।

काली एवं मध्य काली मिट्टी :-

- पानी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है।
- मध्यम काली मुख्य रूप झालावाड़, कोटा, बारां, बूँदी में पायी जाती है।
- इसमें आयरन, जिंक मैंगनीज, कैल्शियम व पोटाश की मात्रा अधिक।
- इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण अधिक पैदावर होती है।
- कृषि हेतु उपयोगी।
- कपास की फसल हेतु उपयुक्त।
- राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में यह मिट्टी ड्रेकन ट्रैप के बेसाल्ट लावा के क्षरण से बनी है।
- कपास, गन्ना चावल, चना, गेंहू, उड़द आदि के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त।
- इस मिट्टी का जल अपरदन अधिक।

मिश्रित लाल व काली मिट्टी :-

- दक्षिण-पूर्वी भाग में विस्तार।
- भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर।
- साधारण उपजाऊ।
- कैल्शियम, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन की कमी।
- मक्का व कपास की खेती हेतु उपयुक्त।

मिश्रित-लाल पीली मिट्टी -

- विस्तार-सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सिरोही मुख्य रूप से लोहे कणों के कारण इनका रंग लाल व पीला
- यह ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस चट्टानों के टूटने से बनती है।
- बनास नदी बेसिन में।

लाल-दोमट मिट्टी-

- विस्तार - उदयपुर तथा डूंगरपुर जिले के मध्यवर्ती भाग व दक्षिणी भाग में।
- यह प्राचीन स्फटकीय और कायान्तरित शैलों से निर्मित।
- लौह कणों की अधिकता के कारण लाल।
- पौटाश तथा चूना पर्याप्त मात्रा में।
- नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की कमी।
- मक्का की फसल हेतु उपयुक्त।
- जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी -
- विस्तार-पूर्वी मैदानी भागों में।
- अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़।
- उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपजाऊ।
- जल धारण की अधिक क्षमता।
- नदी नालों के किनारे तथा उनके प्रवाह क्षेत्र में।
- नमी की अधिकता।
- नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में।
- गेंहँ व चावल हेतु उपयुक्त।

भूरी मिट्टी -

- विस्तार - अरावली के पूर्वी भाग।
- बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में।
- भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बँदी, सवाई माधोपुर।
- नाइट्रोजन व फॉस्फोरस तत्वों का अभाव।

सिरोजम मिट्टी या धूसर मरूस्थलीय मिट्टी -

- विस्तार - बांगड़ प्रदेश
- पाली - नागौर, जालौर
- लूनी बेसिन में
- बारानी कृषि हेतु उपयुक्त।
- पीला भूरा रंग।

लेटेराइट मिट्टी:-

- प्रतापगढ़, बांसवाड़ा।

निर्माण कैप्सूल -

- देश की व्यर्थ भूमि का 20 प्रतिशत राजस्थान में।
- मिट्टी में लवणीयता की समस्या दूर करने हेतु रॉक फॉस्फेट का प्रयोग।
- मिट्टी की क्षारीयता की समस्या दूर करने हेतु जिप्सम का प्रयोग।
- राज्य में वायु से मृदा अपरदन का क्षेत्रफल सबसे अधिक, उसके बाद जल से मृदा अपरदन।
- मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक चम्बल नदी से।
- खड़ीन- मरूभूमि में रेत के ऊँचे-ऊँचे टीलों के समीप कुछ स्थानों पर निचले गहरे भाग बन जाते है। जिनके बारीक कणों वाली मटियारी मिट्टी का जमाव हो जाता है।

- तलाब में पानी सूखने पर जमीन की उपजाऊ मिट्टी की परत को पणों कहते है।
- राजस्थान में सर्वाधिक बंजर व अकृषि भूमि उदयपुर में है।
- जैसलमेर दूसरे स्थान पर है।
- राज्य की प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारतीय क्षारीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला नाम से स्थापित की गई।
- भूमि की सेम समस्या मुख्य रूप से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले में।
- हनुमानगढ़ सेम समस्या निदान के लिए इकोडच परियोजना नीदरलैण्ड (हॉलैण्ड) की सहायता से चलाई जा रही है। नीदरलैण्ड आर्थिक एवं तकनीकि सहायता प्रदान कर रहा है।
- ऊसर भूमि के लिए हरी खाद तथा गोबर का उपयोग करना चाहिए।
- राजस्थान में लगभग 7.2 लाख हैक्टेयर भूमि क्षारीय व लवणीय है।
- **आवरण अपरदन**- जब घनघोर वर्षा के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है।
- **धरातली अपरदन**- पहाड़ी एवं सतही ढ़ालों की ऊपरी मूल्यवान मिट्टी को जल द्वारा बहा ले जाना।
- **नालीनूमा अपरदन**- जब जल बहता है। तो उसकी विभिन्न धारायें मिटट्री को कुछ गहराई, तक काट देती हैं परिणाम स्वरूप धरातल में कई फुट गहरी नालियां बन जाती है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर में इस प्रकार अपरदन पाया जाता है।
- **धमासा (ट्रफोसिया परपूरिया)**- एक खरपतवार है जो जयपुर क्षेत्र में अधिक प्राप्त।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ भूमि 37.30 प्रतिशत जैसलमेर में है।
- उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि राजसमंद में है।
- दक्षिणी -पूर्वी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा वनों को काटकर जिसे मिट्टी का अपरदन वालरा अथवा झूमिंग कृषि कहते हैं।

राजस्थान की मिट्टीयों का नई पद्धति से वर्गीकरण

इसमें मृदा की उत्पत्ति के कारकों को आवश्यकतानुसार महत्व देते हुए अधिक महत्वपूर्ण मृदाओं में मौजुद गुणों को दिया जाता है।

एरिडोसोल्स :-

- वह खनिज मृदा जो अधिकतर शुष्क जलवायु में पायी जाती है।
- चूरू, सीकर, झुनूनँ, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर जिलों में।

अल्ी सोल्स -

- जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र।
- जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमन्द, उदयपुर डूँगरपुर, बूँदी, कोटा, बारां, झालावाड़।
- मटियारी मिट्टी की मात्रा अधिक।

एन्टी सोल्स -

- पश्चिमी राजस्थान में।
- ऐसा मृदा वर्ग जिसके अंतर्गत भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है।
- पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है।
- इसका रंग प्रायः हल्का पीला-भूरा

इनसेप्टी सोल्स :-

- अर्द्धशुष्क से आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में।
- शुष्क जलवायु में पूर्णतः अभाव।
- सिरोही, पाली, राजसमन्द, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़।
- जलोढ़ मृदाओं के मैदान में भी।

वर्टीसोल्स :-

- काली व रेगुर मिट्टी का क्षेत्र।
- झालावाड़, बारां, कोटा, बूँदी।
- इसमें अत्यधिक क्ले उपस्थिति होने के कारण इसमें मटियारी मिट्टी की विशेषताएं पायी जाती है।

राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

- जयपुर - सामान्य मिट्टी प्रयोगशाला।
- जोधपुर - समस्याग्रस्त मिट्टी प्रयोगशाला।
- राज्य में केन्दीय भू-संरक्षण बोर्ड कार्यालय - कोटा, जोधपुर।

राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ

मीणा

- राजस्थान की जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति का प्रथम स्थान (49 प्रतिशत) है।
- मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मछली है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन्हें भगवान मत्स्यावतार का रूप माना जाता है।
- राज्य में मीणा जनजाति का 50 प्रतिशत से अधिक भाग पाँच जिलों- जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली तथा उदयपुर जिलों में निवास करता है।
- मीणा जनजाति में 24 गौत्र (खापें) है जबकि आचार्य मुनि मगन सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में मीणों के 5200 गौत्र होने की पुष्टि होती है।
- मीणा जनजाति के 2 वर्ग है-1 जमींदार, 2 चौकीदार। जमींदार मीणा अपने आपकों अधिक श्रेष्ठ मानते हैं।
- राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जयपुर जिले में निवास है।
- मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जनजाति है।
- मीणा जाति में पंचायत के मुखिया को पटेल तथा देवी-देवताओं को **बुझ देवता** कहा जाता है।
- मीणा जाति में विवाह विच्छेद का विशेषाधिकार मुख्यतया पुरूषों को प्राप्त होता है। जिसके अंतर्गत पति द्वारा दुपट्टे का कुछ भाग फाड़कर स्त्री के हाथ में देने से पति-पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं।
- मीणा जनजाति में बंटाईदारी कृषि व्यवस्था का प्रचलन है।
- मीणा जाति में पुत्र जन्म पर थाली बजाकर तथा पुत्री के जन्म की सूचना सूप बजाकर दी जाती है।
- मीणा जाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है।
- राजस्थान में आजादी के बाद मीणा जनजाति में सर्वाधिक शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हुआ है। यह अन्य जनजातियों के लिए प्ररेणा दायक हो सकता है।

भील

- जनजातियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान में इसका दूसरा स्थान है।
- राजस्थान में भील उदयपुर (सर्वाधिक), बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़पुर आदि जिलों में मुख्य रूप से निवास करते हैं।
- भील द्रविड़ भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ तीर चलाने वाला व्यक्ति होता है।
- कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र के नाम से संबंधित किया।
- भील पुरूष **फालू** पहनते है, लंगोटिया भील कमर पर लंगौटी बांधते हैं, जिसे **खोयतु** तथा इनकी स्त्रियाँ घुटने तक नीचा घाघरा पहलती है जिसे कछावू कहते है।
- भीलो के घरों को **कू** कहा जता हैं तथा बहुत से झोपड़े मिल कर **पाल** कहलाते है इसका मुखिया **पालवी** कहलाता है।
- भीलों के छोटे गांव को **फला** व बड़े गांव को **पाल** कहा जाता है। समस्त पाल का मुखिया **गमेती** कहलाता है।
- भीलों के गांव का **मुखिया तदवी** या **वंसाओं** भी कहलाता है।
- भील केसरियानाथ (ऋषभदेव) के चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते।
- फाइरे- फइरें भीलों का रणघोष है।
- भील क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर प्राप्त की गई भूमि में वर्षा काल में की जाने वाली खेती को चिमाता तथा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को **दजिया** कहा जाता है।
- डूँगरपुर जिले में **बेणेश्वर** और **घोटिया अम्बा** के भील मेले प्रसिद्ध है।
- मेवाड़ तथा उत्तर-पूर्व गुजरात में भीलों में विवाद की अनूठी परम्परा है, इसमें देववृक्ष, पीपल, सागवान, साल एवं बांस के पेड़ों को साक्षी मानकर भील युवक-युवती हरज व लाड़ी अर्थात् पति-पत्नी बन जाते हैं। इस प्रकार के गठबंधन को **हाथी वैडो** कहा जाता है।
- होली भीलों का सबसे महत्वूपर्ण त्यौहार हैं। डूँगरपुर जिले के भीलूड़ा गांव में पत्थरों में होली-खेलने की परम्परा हैं जिसे **रोड-खेलना** कहते हैं।।

भीलों से संबंधित अन्य महत्वूपर्ण तथ्य एवं शब्द -

- **बोलवा**-मार्गदर्शक, भील को बोलावा कहाँ जाता है।
- **पाखरिया**- यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार दे तो वह पखरिया कहलाता है। यह सम्मान सूचक शब्द है।
- **अटक**- भीलों के कुल देवता को टोटम कहा जाता है।
- **कायता**-भीलों में मृत्यु भोज कायता (काट्टा) कहलाता है।
- **हलमा**- भीलों में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की परम्परा हलमा कहलाती है।
- **डाम**- भीलों में बीमारियों को उपचार डाम लगाकर करते हैं। इसमें बीमार व्यक्ति की नस विशेष पर जलता हुआ तार, ठीकरी, लोहा आदि रखकर डाम लगाई जाती है। उस पर आक का दूध लगाया जाता है। भीलों में एक कहावत प्रचलति है। ''के राखे राम, के राखे डाम'
- **छेड़ा फाड़ना**-भीलों में तलाक को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। यह गांव के मुखिया की उपस्थिति में होता है।
- **ढेपाड़ा**-भील पुरूषों द्वारा सिर पर पहले जाने वाली तंग धोती।
- **पोत्या**- भील पुरूषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला सफेद साफा।
- **सिंदूरी**- विवाह के अवसर पर भील दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी।
- **पिरिया**- विवाह के अवसर पर भील दुल्हनों द्वारा पहने जाले वाला पीले रंग का लहंगा।
- **मौताणा**- उदयपुर संभाग के आदिवासियों में प्रचलित एक सामाजिक परम्परा, जिसके तहत यदि किसी आदिवासी की कोई हत्या कर देता हैं तो हत्या करने वाले पक्ष से मृत व्यक्ति की हत्या के बदले जुर्माना वसूला जाता है।
- **चढ़ोतरा**-यदि हत्या करने वाला पक्ष हर्जाने की रकम नहीं अदा करे तो पीड़ित पक्ष के समर्थक हत्या करने वालों पर सामुहिक रूप से चढ़ाई कर देते है, तथा खूनी संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। इसे चढ़ोतरा कहते हैं।

गरासिया

- मीणा व भील के बाद गरासिया राज्य में तीसरी बड़ी जनजाति है।
- गरासिया चौहान राजपूतों के वंशज माने जाते हैं।
- दक्षिणी राजस्थान में मुख्यत: पाई जाने वाली इस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या सिरोही जिले की आबूरोड़ तथा पिण्डावाड़ा तहसीलों में हैं।
- गरासियों में तीन प्रकार के विवाह हैं-मौर बंधिया, विवाह, पहरावना विवाह, और ताणना विवाह।
- गरासिया जनजाति के त्यौहार आखा तीज से आरम्भ होते हैं।
- इस जनजाति का सबसे बड़ा मेला मनखां रो मेलो (आम आदिवसी मेला) कहलाता है। इसे सियावा का गौर मेला भी कहते है। ये आबू रोड़ के पास लगता है।
- गरासिया लोग अपने पूर्वजों की आत्मा शांति हेतु प्रस्तर प्रतिमा बनवाकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधिवत प्रतिष्ठापित करते हैं। इन प्रतिमाओं को हूरा या मोगी कहते हैं।
- गरासिया गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है।
- घेर- गरासिया लोगों के कच्चे घर होते हैं, जिन्हें वह घेर कहते है।
- सोहरी- गरासिया के अनाज भंडारण के कोठियों को सोहरी कहा जाता है।
- हारी भावरी-गरासिया समाज की सहकारी खेती परम्परा।
- हेलरू-गरासिया युवक-युवतियों की मिली-जुली संस्था।
- वालरा-स्थानान्तरित कृषि मेक- गरासियों में मृत्यु भोज।
- गरासियों के क्षेत्रों में लगने वाले प्रमुख मेले- सियावा का गौर मैला, कोटेश्वर मेला, नेवटी का मेला, भखरवागजी का मेला, अम्बाजी का मेला, देवला का मेला।

सहरिया

- राज्य में सहरिया जनजाति मुख्यत: बारां जिले की किशनगंज एवं शहबाद तहसील में निवास करती है।
- सहरिया जनजाति के गौत्र राजपूतों के समान हैं यथा चौहान देवड़ा, सोलंकी, बाघेला आदि।
- सहरिया जनजाति के गांव सहरोल तथा बस्ती सहराना कहलाती है। सहरिया गांव की सबसे छोटी इकाई फलां कहलाती है।
- सहरिया जनजाति में मुख्या को कोतवाल कहते हैं।
- सहरिया जाति में होली के अवसर पर फाग और राई नृत्य तथा दीपावली पर हींडा गाने का प्रचलन है।
- हाड़ौती अंचल में भरने वाला सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है।
- सहरिया तेजाजी की भी पूजा करते हैं।

डामोर

- डामोर जनजाति मुख्यत: राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में डूँगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति और बांसवाड़ा जिले में गुजरात की सीमा पर निवास करती है। यह राजस्थान की कुल जनजाति जनंसख्या का 0.7 प्रतिशत है।
- डामोर स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद नातरा करती है।
- डामोर जनजाति के पुरूष स्त्रियों की भांति गहने पहनते हैं।
- डामोर जनजाति की जाति पंचायत के मुख्या को मुखी कहते है।
- छेल बावजी का मेला (गुजरात के पंचमहल जिले में आयोजित) तथा गयारस सकी रेलगाड़ी का मेला (डूँगरपुर में आयोजित) डामोर जनजाति के प्रमुख मेंले है।
- डामोर जनजाति में भी सहरिया जनजाति की तरह बहु-पत्नि प्रथा का प्रचलन है।
- होली के अवसर पर डामोर लोगों द्वार आयोजित कार्यक्रम को चाड़िया कहते हैं।

सांसी

- सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमहल नामक व्यक्ति से हुई मानी जाती है। सांसी जनजाति राज्य में भरतपुर जिले के कुछ भागों में खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है। भरतपुर में सांसी सबसे अधिक संख्या में निवास करते है।
- सांसी जनजाति दो भागों में विभक्त है-बीजा और माला।
- सांसी जनजाति लोमड़ी व सांड का मास सर्वाधिक पसन्द करती हैं।
- सांसी जनजाति में विवाह खोपरे की गिरी में लेन-देन मात्र से हो जाता है।

कंजर

- कंजर एक घुमंतु जाति है। जो अपराध वृत्ति के लिये प्रसिद्ध है।
- कंजर नाम संस्कृत शब्द काननचार का अपभ्रंश है जिसका अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाला।
- राजस्थान में यह जाति कोटा, बारॉं, बूँदी, झालवाड़ जिलों में निवास करती है।
- कंजर चौथमाता व हनुमानजी को अपना आराध्य देव मानते हैं।
- कंजर परिवारों में मुखिया को पटेल कहते हैं।
- कंजर जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है।
- कंजर व्यक्ति के मरते समय उसके मुंह में शराब की बूँदे डाली जाती है।
- कंजर व्यक्ति अपराध करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे ये पाती मांगना कहते हैं।
- कंजर जाति को मोर का मांस सर्वाधिक प्रिय होता है।

कथौड़ी जनजाति

- मूलत: यह भील है, परन्तु कत्था बनाने के कारण इन्हें कथौड़ी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के खानदेश के रहने वाले थे, जिन्हें कत्था निर्माण करने वाले बोहरा मुसलमान ठेकेदारों ने उदयपुर के फलासिया, कोटड़ा खैरावाड़ा तहसीलों में बसाया।
- मुख्य व्यवसाय खैर के वृक्षों की छाल से कत्था बनाना।
- जनजाति के दल का मुखिया भोपा या पटेल होता है। इस जनजाति में मृत को जलाने के स्थान पर दफनाया जाता है।
- ये कालिका माता की पूजा करते है।

पटेलिया जनजाति

- यह राजस्थान की प्रमुख अल्पसंख्यक जनजाति है, जो मुख्यत: कोटा, बारॉं, झालावाड़ जिले में निवास करती है।
- राजस्थान में यह प्रवासी जनजाति है। मूल रूप से यह मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में निवास करती है।

जनजातियों में प्रचलित विभिन्न रीति-रिवाज

- **आटा-साटा**- विवाह की इस रीति में लड़की के बदले लड़की दी जाती है।
- **लीला मोरिया**- विवाह के इस संस्कार में दूल्हें के घर पर दूल्हें को बुलाकर खाट पर बैठाकर इसके चारों तरफ नृत्य किया जाता है।
- **बड़ालिया** - माता-पिता द्वारा तय किये गये वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला मामा या फूंका को बड़ालिया कहा जाता है।
- **हगा-हगवाड़िया**- वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए आदिवासी लोग अपनी कौम के दो वर्गों में विभक्त करते है। हगावर्ग में शामिल व्यक्ति के साथ विवाह धर्म विरूद्ध है, जबकि हगवाड़िया के साथ वैवाहिक संबंध वैद्य होते हैं।
- **मारू-ढोल**- संकट के समय लोगों को एकत्रित करने के लिए बजाया जाने वाला ढोर।
- **गरिये का ढोल**- किसी दुर्घटना पर लोगों को सावधान करने के लिए बजने वाला ढोल।

जनजाति क्षेत्रिय विकास कार्यक्रम

- 1947-75 से प्रारम्भ जनजाति उपयोजन में राज्य के दक्षिण-पूर्व में स्थित बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, (अरनोद वं प्रतापगढ़ तहसीलें) तथा सिरोही (आबूरोड़ खण्ड) जिले की 23 पंचायत समितियां सम्मिलित हैं वर्तमान में प्रतापगढ़ जिला बन जाने के कारण अब ये योजना 6 जिलों में कार्यरत है।

परिवर्तित क्षेत्र-विकास उपगम (माड़ा)

- 1978-79 से प्रारम्भ इस कार्यक्रम में 16 जिलों में माड़ा खण्डों का गठन किया गया, ये है-अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूँदी, जयपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, झालावाड़ कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, करौली, बारॉ सिरोही, टोंक व उदयपुर।
- माड के अंतर्गत लघु सिंचाई, सामुदायिक पम्पसेट, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, व्यावसायिक शिक्षा, दुकानों के लिए अनुदान, पेयजल सुविधाएँ, चिकित्सा आदि सामुदायिक विकास के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

सहरिया विकास कार्यक्रम

- 1977-78 से प्रारम्भ यह कार्यक्रम बारॉ जिले के किशनगंज एवं शहबाद तहसीलों की सहरयिा जनजाति के विकास के लिये अपनाया गया है।
- इस कार्यक्रम में कृषि, पशु-पालन कुटीर उद्योग, वानिकी, शिक्षा, पोषण, पेयजल ग्रामीण, विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि पर धनराशि व्यय की जाती है।

राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकार संघ

(राजस संघ)

- 27 मार्च, 1976 में स्थापित राजस संघ का मुख्य कार्यालय उदयपुर में हैं तथा संघ के 6 क्षेत्रीय कार्यालय-उदयपुर, डूँगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, तथा प्रतापगढ़ में हैं। आबूरोड़ में सहायक क्षेत्रीय प्रबंध कार्यालय है।
- इसके प्रमुख उददेश्य में आदिवासियों को बिचौलियों, व्यापारियों तथा साहूकारों के शोषण से मुक्त कराना तथा सहकारी संगठनों के माध्यम से जनजाति लोगों की निर्धनता को दूर करना है।
- जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राजस संघ द्वारा संचालित मत्स्य बीज फार्म जयसमंद, टामटिया और सोम कागदार में है।

माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

- उदयपुर में आयंड नदी के किनारे स्थित इस संस्थान की स्थापना
- 1 जनवरी, 1964 को की गई। 1979 में यह संस्थान जनजाति विकास निगम के अधीन चला गया

Special Fact of Rajasthan

- सीधा लाभ हस्तान्तरण (DBT) की शुरूआत करने वाला प्रथम राज्य।
- उद्योग आधार का पंजीयन प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में राजस्थान देशभर में पहले स्थान पर।
- राज्य का सौर विद्युत ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान (1270 मेगावाट)। सौर ऊर्जा की सबसे कम दर प्राप्त।
- सम्पूर्ण राज्य में LED आधारित ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइट लगवाने वाला प्रथम प्रदेश।
- ई-मित्र के माध्यम से सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी प्रारंभ करने वाला प्रथम प्रदेश।
- उचित मूल्य दुकानों को ग्रामीण मल्टीब्रान्ड आउटलेट (अन्नपूर्णा) में बदलने वाला प्रथम राज्य।
- परिवाद निस्तारण की एकीकृत ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला प्रथम एवं एकमात्र राज्य (राजस्थान सम्पर्क)।
- 61 मुख्य अधिनियम एवं 187 संशोधन अधिनियमों को विलोपित करने वाला पहला राज्य।
- रोजगार सृजन के लिए श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन करने वाला अग्रणी राज्य।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना** का क्रियान्वयन करने वाला प्रथम प्रदेश।
- देश में पहली बार किसी राज्य में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत **दुर्घटना बीमा योजना** में 5 लाख रूपये का बीमा लाभ देने की शुरूआत।
- योजना में प्रीमियम की आधी राशि सहकारी बैंकों द्वारा वहन। अब तक 20 लाख से अधिक किसान पंजीकृत। वर्तमान में फसली ऋण के तहत **दुर्घटना बीमा की देश में यह सबसे बड़ी योजना।**
- जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेंशनरों के लिए दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा।
- उदयपुर संभाग में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित।
- ऊँट को राज्य पशु घोषित।
- काउण्टर मैग्नेट सिटी का उद्देश्य ऐसे शहरी क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करना है, जिनके कारण दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में जनसंख्या के पलायन को रोका जा सके। इसके तहत एनसीआर से दूर ऐसे शहरों का चयन किया जाता है, जिनमें एनसीआर की तरह आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं हो।

एसबीसी व ईसीबी आरक्षण विधेयक

एसबीसी को 5 प्रतिशत व आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक-2015 और राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिण संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आंरक्षण) विधेयक-2015 विधानसभा में पेश किए।

प्रतिपक्ष के हंगामे के बीच 22 सितम्बर, 2015 को राज्य विधानसभा में चार बिल पास हुए। एसबीसी में शामिल गुर्जरों सहित पांच जातियों को पांच प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण देने के दो अलग-अलग विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। यह आरक्षण सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के लिए लागू होगा। इन विधेयकों के पारित होने के साथ ही राज्य में आरंक्षण की व्यवस्था **68 प्रतिशत** तक हो गई है।

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग को आरक्षण

गुर्जरों के साथ अन्य चार जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही थी और लंबे समय से आरक्षण की मांग करने रोकने जैसे प्रदर्शन भी किए गए। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ही राज्य सरकार यह विधेयक लेकर आई। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही इससे पहले पारित अधिनियम 2008 (2009 का अधिनियम संख्या 12) निरसित हो जाएंगे।

एसबीसी में शामिल हैं ये पांच जातियां :

1. बंजारा, बालदिया, लबाना,
2. गाडिया लोहार, गाडोलिया,
3. गूजर, गुर्जर
4. राईका, रैबारी, देवासी
5. गडरिया, गाडरी, गायरी।

आरक्षण कहां मिलेगा : शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। एसबीसी की जातियों में आने वाले क्रीमीलेयर से संबंधित व्यक्ति नियुक्तियों में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद या एकल पद आरक्षण लागू नहीं होगा।

ओबीसी में क्रीमीलेयर की सीमा परिवर्तन-2015

राजस्थान में करीब 2 करोड़ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आबादी के 30 लाख से अधिक युवाओं के लिए राज्य सरकार ने 16 सितम्बर, 2015 के एक आदेश से ताले लगा दिए है। राजस्थान में 2.5 लाख से अधिक आय वाला ओबीसी श्रेणी का युवा सामान्य वर्ग का माना जाता है। जबकि दूसरे राज्यों में 6 लाख रूपए वार्षिक आय पर ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का माना जाता है। दूसरी तरफ नेशनल ओबीसी कमिशन ने 15 दिन पहले ही क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ा कर 10. 54 लाख रूपए करने की मंत्रालय से सिफारिश की है।

पहले राज्य में 4.5 लाख थी क्रीमी लेयर

पिछली गहलोत सरकार ने पहले 22 दिसम्बर, 2010 को एक आदेश जारी कर क्रीमीलेयर की सीमा 2.5 से 4.5 लाख रूपये की थी लेकिन 17 सितम्बर, 2012 को फिर आदेश कर पूर्व के आदेश को अप्रभावी कर दिया। उसके बाद फिर क्रीमीलेयर की सीमा 2.5 लाख रूपए कर दी। इसमें 2.5 लाख से अधिक आय वाले ओबीसी वर्ग के युवाओं के इसी वित्तीय सीमा के आधार पर ओबीसी या क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे है। केन्द्र ने 27 मई, 2013 को आदेश जारी कर क्रीमीलेयर सीमा 4.5 लाख को रिवाइज कर 6 लाख रूपए कर दी थी। इतना ही नहीं इसकी पालना के भी आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि दस साल में क्रीमीलेयर सीमा रिव्यू हो तथा एक बार जिसने आरक्षण का लाभ ले लिया, उसके परिवार की बजाय फिर दूसरे परिवार को आरक्षण मिले।

MAST(मस्त) दूरबीन

विश्व का सबसे बड़ा सोलर टेलीस्कोप मस्त (MAST: Multi Application Solar Telescope) (सौर दूरबीन) उदयपुर की फतेहसागर झील में स्थित 'उदयपुर सौर वैधशाला' में 16 जून, 2015 को लगाया गया है। यह दूरबीन सूर्य के चुम्बकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगी। उदयुपर स्थित इस वैधशाला की स्थापना 1976 ई. में भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन की गयी है। इसके संस्थापक डॉ. अरविन्द भटनागर है तथा यह वैधशाला संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की 'बिग बियर झील' में स्थित वैधशाला के मॉडल के आधार पर विकसित की गयी है।

सौर ऊर्जा में राजस्थान की स्थिति

- सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- यहाँ सर्वाधिक 1264 मेगावट सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ।
- इसके बाद क्रमशः गुजरात (1024 मेगावाट)→मध्यप्रदेश (679)→ तमिलनाडु (419 मेगावाट) हैं।

पिनाक M.K-2

- 28-29 दिसम्बर, 2015 को मल्टी बेरल रॉकेट लांचर पिनाक M.K-2 का पोखरण (जैसलमेर) फील्ड फायरिंग रेंज के चांधन क्षेत्र में सफल परीक्षण किया गया।
- मल्टी बेरल रॉकेट लांचर पिनाक M.K- 2 एक ही बार में 12 रॉकेट छोड़ सकता है और 44 सैकण्ड में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है।
- पिनाक M.K-2 DRDO की ओर से निर्मित स्वदेशी रक्षा संयत्र है।

साल्ट ट्यूरिज्म सेंटर

- **दुनिया का पहला साल्ट ट्यूरिज्म सेंटर** सांभर झील में बनाने पर निर्णय लिया गया।
- सांभर लेक एक रामसर साइट है। अतः इसे चुनते हुए **'स्वदेश दर्शन यो**जना' में इसके लिए 64 करोड़ रूपये की योजना मंजूर की है।

पासा

- **राज्य के 10 जिलों को पासा की शक्तियाँ :** दिसम्बर 2015 में राज्य सरकार ने ड्रग, शराब एवं भू- माफिया सहित कुख्यात अपराधियों पर कार्यवाही के लिए 10 जिलों को आगामी एक वर्ष तक **राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम- 2006 (पासा)** की शक्तियाँ प्रदान की है। इसके तहत् जिला प्रशासन उस किसी भी दुर्दांत अपराधी को एक वर्ष तक जेल में बंद कर सकता है, जिसकी वजह से लोकशांति भंग होने की आशंका रहती है। जयपुर एवं जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और अलवर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, करौली और दौसा को पासा की शक्तियाँ प्रदान की गई है।

वित्तीय साक्षरता के लिए समझौता

- राज्य में ग्राम स्तर पर वित्तीय साक्षरता और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए दिसम्बर 2015 में नाबार्ड एवं अपेक्स बैंक के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत् नाबोर्ड इस कार्य के लिए 75 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा।
- इसी क्रम में राजस्थान देश का प्रथम राज्य बनने जा रहा है जो नाबार्ड के सहयोग से ग्राम स्तर पर लोगो को वित्तीय साक्षरता से बैंको में खाता खुलवाने से लेकर लेनदेन की जानकारी उपलब्ध कराएगा।

प्रत्येक जिले के लिए होगा एक विशेष वन्य जीव

इससे राज्य के प्रत्येक जिलें को एक वन्य जीव के नाम पर एक अलग पहचान मिलेगी और प्रत्येक जिलें की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने जिला स्तरीय वन्यजीव को बचाने एवं संरक्षित करने की दिशा में कार्य करे। राज्य के प्रत्येक जिले के वन्यजीव निम्नलिखित है-

जिला		वन्यजीव
अलवर	→	सांभर
बाँसवाड़ा	→	जलपीपी
बांरा	→	मगर
भीलवाड़ा	→	मोर
बीकानेर	→	भट्टतीतर
चूरू	→	कालातीतर
धौलपुर	→	पंछीरा
जयपुर	→	चीतल
जैसलमेर	→	गोडावण
जालोर	→	भालू
अजमेर	→	खमनौर
बाड़मेर	→	मरूलोमड़ी
भरतपुर	→	सारस
बूँदी	→	सारस
डूँगरपुर	→	जंगली धोक
हनुमानगढ़	→	छोटा कीकीला
झालावाड़	→	मगरोनी तोता
जोधपुर	→	कुरंजा
कोटा	→	उदबिलाऊ
नागौर	→	राजहंस
राजसमंद	→	भेडिया
श्री गंगानगर	→	चिंकारा
सिरोही	→	जंगली मुर्गी
टोंक	→	हंस
करौली	→	घड़ियाल
पाली	→	तेंदुआ
प्रतापगढ़	→	उड़न गिलहरी
स. माधोपुर	→	बाघ
सीकर	→	शाहीन
उदयपुर	→	बिज्जू

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कार्पोरेशन

- राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कार्पोरेशन का होगा पुनर्गठन।
- इसे अब राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेशियल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा।
- उद्देश्य : राज्य के विभिन्न उपक्रमों के पास उपलब्ध आधिशेष राशि बैंको के स्थान पर अब इस कॉपोरेशन के पास सावधि जमा के रूप में रखी जा सकेगी। जिसका उपयोग राज्य के विद्युत कंपनियों तथा अन्य कमजोर यूनिट्स को ऋण देने के रूप में किया जा सकेगा।

राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी

- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जयपुर एग्जीबिशन एण्ड कन्वेंशन सेंटर में
- 5 वर्षों में 500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित।
- **स्टार्टअप** पॉलिसी लाँच करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य (राजस्थान है)।
- नये बिजनेस आइडिया को प्रोत्साहन देना, बिजनेस आइडिया उद्देश्य मंजूर होने पर 10 लाख रूपए तक का ऋण और एक वर्ष तक 10,000 रूपये भत्ता मिलेगा।

सूफी फेस्टिवल

- जयपुर में सम्पन्न हुआ ''सकि सूफी फेस्टिवल''
- आयोजन ETV News के सहयोग से ''फाउन्डेशन ऑफ सकि राइटर्स एण्ड लिटेचर'' द्वारा किया गया।
- इस सूफी महोत्सव में **8** सार्क देशों-भारत, पाकिस्तान, बाँग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका मालदीव एवं अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान के संगीतज्ञो ने भाग लिया,
- महोत्सव में सूफी नृत्य एवं संगीत कविता, बुक रीड़िग, पुस्तक विमोचन और इंटरेक्टिव का उत्कृष्ट मिश्रण था।

आधारभूत संरचना एंव ढाँचागत विकास

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में 0.5 से 2 कि.मी लम्बाई में **c.c** सड़क का निर्माण कर ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित करने के प्रथम चरण में 1984 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1955 की. मी लम्बाई में c.c सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- पूर्व में निर्मित उत्तर-दक्षिण मेगा हाइवे की भाँति **पूर्व-पश्चिम मेगा हाइवे कोरिडोर** विकसित करने के क्रम में पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर योजना के लिए कॉरिडोर चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- इस कॉरिडोर के विकसित होने से -जैसलमेर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व कोटा शहर लाभान्वित होंगे।
- राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम 2015 दिनांक 1.07.15 से लागू हो गया। प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना दिनांक 25.8.2015 को जारी हो चुकी है।

वित्तीय प्रबंधन

- **FRBM ACT** में संशोधनकर राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि पुनः सृजित की गई।
- पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं वर्ष 2015 से 2020 की अवधि के लिए वित्तीय हस्तांतरण के संम्बध में सिफारिश देने के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया।

कर सुधार

- दिनांक **01-07-2015** से समस्त कर निर्धारण ऑनलाइन किये जा रहे हैं।
- समस्त संभागीय कार्यालयों में पी.पी.पी. मोड में डीलर फैसीलिटेशन सेन्टर ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

NIRMAN FACT FILE

- **नाग का सफल परिक्षणः** 43 किलों वजनी, लागत 300 करोड़, इसमे हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक विस्फोटक काम में लिया गया।, आधुनिक टैंक को भेदने की क्षमता।
- **शक्ति 2016** - भारत व फ्रांस की सेना के मध्य युद्धाभ्यास
- **गो-अभ्यारण** बीकानेर में बनाया जाएगा।
- **हाल ही में जो विश्व विद्यालय बंद हुआः** हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। इसका स्थानांतरण अब RU में
- **जनजाति विश्वविद्यालयः** बाँसवाड़ा में व इसका नया नाम अब गोविन्द गुरू जनजाति विश्वविद्यालय होगा।
- **विंडमिल पॉवर प्लांटः** केंद्रिय रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने राजस्थान के जैसलमेर के कोडियार गाँव में स्थापित 26 मेगावाट क्षमता का विंडमिल पॉवर प्लाँट राष्ट्र को समर्पित किया।
- **केरोसिन सब्सिडी योजनाः** 1 अप्रैल से खाते में केरोसिन सब्सिडी योजना की शुरूआत 8 राज्यों के 26 जिलो से होगी। इनमें राजस्थान से कोटा, पाली, व झुंझुनू शामिल हैं।
- रामसिंह पुरा बना राज्य का **पहला स्मोक-लेस गाँव** (बस्सी तहसील में स्थित)
- **राज्य का पहला सौर ऊर्जा प्लांटः** गुजरात की नर्मदा नदी की तर्ज पर हनुमानगढ़ जिले में मैनावाली माइनर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन किया जाएगा। यह देश का दूसरा व राज्य का पहला प्रौजेक्ट होगा।
- **केयर्न इंडिया करेगी राजस्थान ब्लॉक्स में 72 करोड़ डॉलर का निवेश** :तिजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्खनन एवं उत्पादक कंपनी केयर्न इंडिया ने उन्नत तकनीक के जरिए, राजस्थान ब्लॉक में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े इन हैंस्ड ऑयल रिकवरी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा दिसम्बर 2015 में की।
- **झुंझुनू में बनेगा राज्यस्तरीय शौर्य उद्यानः** दिसम्बर, 2015 में राज्य की C.M ने कला एवं संस्कृति विभाग के राज्य स्तरीय शौर्य उद्यान के निर्माण के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह उद्यान राज्य के जाबांज जवानो और वीरो के शौर्य और पराक्रम को संजोने के लिए झुंझुनू जिले मे बनाया जाएगा।
- **राजस्थान उदय योजना में शामिलः** 7 दिसम्बर, 2015 को राजस्थान सरकार ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की UDAY (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) में शामिल करने के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।
- **राज्य उच्च शिक्षा परिषद्** का गठन होगा को स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय में क्रमोन्नत करने विश्वविद्यालय में गुणात्मक तथा आधारभूत ढाँचे में सुधार के प्रस्ताव, नीति निधारण तथा क्रियान्वयन का कार्य करेगी।
- **दृढ़ संकल्पः** रेगिस्तान मे 2 माह तक चला थल सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास।
- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण** की और से 9 नव. 2015 को राज्य के **अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** को देश के पाश्चिमी जोन के सर्वश्रेष्ठ विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में सम्मानित किया गया है।
- सीकर में खुलेगा **मल्टी स्किल ट्रेनिंग** सेंटर।
- दक्षिण आस्ट्रेलिया के साथ **सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप समझौताः** रिसर्जेन्ट राजस्थान समित के दौरान सम्पन्न, इसके तहत दोनों राज्य ऊर्जा, पेयजल पर्यावरण-प्रबंधन, खाद्यान, शिक्षा, कृषि, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, प्रबंधन, कौशल विकास एंव प्रशिक्षण, पर्यटन एवं खेल के क्षेत्र में व्यापार और निवेश के अवसर तलाशने के लिए साझा कार्य योजनाएँ बनाएँगे।

- **जालौर में बनेगा अन्तर्देशीय बंदरगाह :** उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास तथा विनिर्माण गतिविधियो को बढ़ावा देने के लिए जालोर में अन्तर्देशीय बंदरगाह बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत् अरब सागर में मोरी खाड़ी और जालोर के बीच एक नहर बनाई जाएगी।
- हेरीटेज अवॉर्ड से अलंकृत दिल्ली स्थित एतिहासिक पुस्तकालय-''मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय'' ने नव. 2015 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए।
- दिल्ली जयपुर के मध्य बनेगा **ग्रीन एक्सप्रेस वे:** प्रस्तावित **एक्सप्रेस** हाइवे की लम्बाई 261 कि.मी होगी और यह दिल्ली के इंदिरा गाँधी हवाई अड्डे से शुरू होकर वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर दौलतपुर में समाप्त होगा।
- **हाइवे विलेज :** चित्तौड़गढ़ में बनेगा देश का पहला **हाइवे विलेज**, इन हाइवे विलेज में हेलिपेड, होटल, रेस्टोरेंट जैसी नगरीय सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।
- **राजस्थान को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी राज्य का पुरस्कार:**30 सितम्बर 15 को इंस्टीटयूट ऑफ कम्पिटेटिवनेस एंव प्रतिष्ठित समाचार-पत्र मिंट के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। क्योंकि राजस्थान का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।
- **राजस्थान शिक्षक गौरव सम्मान :** इमरान खान को जिन्होने शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी और क्रांतिकारी बदलाव हेतु महत्वपूर्ण मोबाइल एप बनाये।
- **माणक अलंकरण:** खोजपूर्ण एवं रचनात्मक पत्रकारिता हेतु जोधपुर के एम. आई. जाहिर को।

चर्चित व्यक्ति

अपूर्वी चंदेला

- 5 जून 16 को 10 मीटर एयर रायफल स्पर्द्धा में 211.2 अंक हासिल कर विश्व रिकार्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता
- 7 जनवरी 16 को 10 मीटर ट्राई सीरीज स्पर्द्धा में 208.9 का स्कोर कर एक स्वर्ण पदक जीता।
- जनवरी 16 में स्वीडन के साहजो में आयोजीत स्वीडिस ग्रां.पी. में उन्हे ''शूटर ऑफ द टूर्नामेंट'' चुना गया।
- अपूर्वी गत वर्ष अप्रेल में कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी हैं।

सीमा सिहोरिया व **जगदीश चौधरी** तीरंदाजी खेल से संबधित।
महावीर सिंह - शुटिंग से संबंधित
शकुंत चौधरी - एथलीट (शॉटपुट)
मनन चतुर्वेदी : राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग'' की अध्यक्ष नियुक्त, कार्यकाल 3 वर्ष के लिए (नियुक्ति 6 जनवरी 16), जयपुर स्थित ''सुरमन संस्थान'' की संचालिका है।
रघुवेन्द्र सिंह राठौड़: राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश, दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (NGT) की मुख्य पीठ में सदस्य नियुक्त 18 जनवरी 2016 को
पंकज पटेल: IIM उदयपुर के चेयरमैन नियुक्त, उद्यमी।
सुंदरलाल: विलानी भाजपा विधायक ''राज्य अनुसूचित जाति आयोग'' के अध्यक्ष नियुक्त (17 अक्टूबर 15 को)
सुमन शर्मा: राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त (17 अक्टूम्बर 15 को)।
निशा गुप्ता: राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नियुक्त, 26 अक्टूबर 2015 का।
चंदा जाट : उदयपुर के फलीचड़ा गाँव की बालिका, ताइवान में अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 6 से 13 अक्टूबर 2015 तक चले कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
इकबाल सिक्का: उदयपुर के शिल्पकार, 465 फीट लम्बे फैक्स रोल पर हस्तलिखित सामाजिक उपन्यास 'अनोखा दहेज' को इंडिया बुक ऑफ रिकार्डस में दर्ज किया यगा।
लीना शर्मा व भक्ति शर्मा: उदयपुर की तैराक (माँ-बेटी) इन्होने 2008 में एक साथ इंग्लिश पनैल पार किया।
प्रकाश : 19 अक्टूबर 15 को ''राज्य मानवाधिकार आयोग'' का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
सुरेश चौधरी: Ret.IPS , राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। 19 अक्टूबर 15 को।
चंद्रमोहन मीणा एंव आशुतोष शर्मा: 19 अक्टूम्बर 2015, को Ret. IPS चंद्रमोहन मीना व वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा को सूचना आयुक्त नियुक्त किया। जबकि P.S. अग्रवाल पहले से ही सूचना आयुक्त है।

राजस्थान की नवीनतम योजनाएँ एवं कार्यक्रम

बेटी बचाओं. बेटी पढ़ाओ अभियान

- देश में घटते हुए शिशु लिंगानुपात की प्रवृत्ति को देखते हुए 22 जनवरी, 2015 को भारत सरकार द्वारा 'बेटी बचाओं **बेटी पढ़ाओं अभियान**' की शुरूआत की गयी है। यह योजना भारत में असंतुलित शिशु लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारम्भ की गयी है।
- इस अभियान में राजस्थान के 10 जिलों-अलवर, **भरतपुर, धौलपुर, दौसा, झुंझुनूँ, सीकर, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर एवं श्रीगंगानगर** को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान में वर्तमान में शिशु-लिंगानुपात 888 है।
- (जनगणना-2011)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

- राजस्थान सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना **13 दिसम्बर 2015** से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी को समस्त सुविधाएँ अन्तरंग (IPD) ईलाज हेतु उपलब्ध होगी तथा कैशलेस होंगी। प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिह्नित सामान्य बीमारियों हेतु रू 30 हजार तथा चिह्नित गंभीर बीमारियों हेतु रू 3.00 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा।
- योजना के तहत चिकित्सा प्रक्रिया से पूर्व 7 दिन तथा छुट्टी पश्चात् के 15 दिन की चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा में कवर होगी।
- हृदय रोग तथा अत्यधिक आघात की स्थिति में 100 से 500 रू तक प्रति परिवार प्रति वर्ष यात्रा भत्ता भी बीमा राशि में शामिल किया गया है।
- योजनान्तर्गत आने वाले लाभार्थी के पास भामाशाह कार्ड होना वांछनीय है। भामाशाह कार्ड ना होने की स्थिति में बीमा लाभ NFSA अथवा RSBY से संबंधित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी दिया जा सकेगा।
- इस योजना की घोषणा राजस्थान सरकार के बजट 2014-15 की गई थी।
- इस योजना का लाभ भामाशाह कार्ड मिलने के साथ-साथ मिलने लगेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग **67 प्रतिशत** परिवार लाभान्वित हो सकेंगे।

कौशल शक्ति योजना-2014

- इस योजना के तहत हिताधिकारियों (पंजीकृत श्रमिकों) के एक पुत्र/पुत्री को राज्य में संचालित आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्नीक संस्थानों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहायता प्रदान की जाती है
- छात्र/छात्राओं को आई.टी.आई/पॉलिटेक्नीक में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 5-8 हजार रूपये तक प्रतिवर्ष कौशल विकास प्रोत्साहन राशि देय है।
- इस योजना का संचालित राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- राज्य सरकार की इस योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में राज्य की समस्त कृषि जोतों (खेतों) को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाना है।
- इस योजना का देश में शुभारम्भ प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी ने** 19 फरवरी, 2015 को सूरतगढ़ (श्री गंगानगर राजस्थान) से किया गया है। इसके तहत देश के 14 करोड़ किसानों को **मृदा स्वास्थ्य कार्ड'** प्रदान किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान

- राजस्थान की विभिन्न जल संसाधन संबंधी समस्याओं के मददेनजर विभिन्न विभागों के समन्वय से एवं राज्य सरकार द्वारा पृथक से बजट उपलब्ध करवाकर इन समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु **''मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान''** प्रारम्भ किया गया है।
- इस अभियान की अवधि 4 वर्ष रखी गयी है। अभियान के तहत राजस्थान के 21,000 गाँव लाभान्वित होंगे। इसमें गाँवों को चयन करके गतिविधियों का चयन, भूमि के प्रकार एवं उपयोग, ढलान, वर्षा जल की उपलब्धता आदि का आंकलन किया जायेगा एवं इस हेतु योजना, ग्रामवासियों के साथ मिलकर तैयार की जायेगी, इसमें जीआईएस एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों की मदद भी ली जायेगी।

ग्रामीण गौरव पथ योजना

- वर्ष 2014-15 के बजट में घोषित इस योजना के तहत राज्य के जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी **ग्राम पंचायतों** में एक आदर्श सड़क **'ग्रामीण गौरव पथ'** का निर्माण किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.)

- राजस्थान राज्य में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी) के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल 08 जिलों के 10 ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ किशनगढ़बास, रामगढ़, तिजारा (अलवर) नगर, कामां (भरतपुर), चौहटन (बाड़मेर), हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़), सम, सांकड़ा (जैसलमेर) एवं तीन कस्बे (मकराना, गंगापुर सिटी एवं टोंक) शामिल किये गये हैं।
- इस योजना के तहत मानसरोवर (जयपुर) में 100 अल्पसंख्यक बालिकाओं के अध्ययन हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (MAGPY)

- निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मदद्गार प्रक्रियाओं में तेजी लगाना।
- आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना, जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिले।

योजना की पात्रता :-

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक आदर्श ग्राम पंचायत विकसित की जायेगी।
- चयनित ग्राम पंचायत मैदानी क्षेत्र में 3 से 5 हजार तथा जनजाति व रेगिस्तानी क्षेत्रों में 1 से 3 हजार की आबादी की होनी चाहिए।
- चयनित ग्राम पंचायत विधायक (स्वय/दम्पत्ति) की ग्राम पंचायत नहीं होगी।

श्री योजना (SHREE)

- प्रारम्भ :- वर्ष 2014-15 में राज्य की बजट घोषणानुसार

उददेश्य :-

- श्री योजना (S.H.R.E.E.) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की 5 मूलभूत आवश्यकताओं-
  S- ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण, तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन
- H-स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता
- R-गॉवों की आन्तरिक सड़के मय नाली निर्माण
- E-शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधाओं का विकास
- E-ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था को चिह्नित कर सुनियोजित विकास किया जाना है।

पात्रता :-

- श्री योजना अंतर्गत सम्मिलित विभागों द्वारा प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय, 5000 या अधिक आबादी वाले गॉवों में वर्तमान में उपलब्ध 5 मूलभूत आवश्यकताएँ चिह्नित किया जाना है।

लक्ष्य :-

- आगामी 15 वर्ष अर्थात् 2030 ई. तक समस्त ग्रामीण क्षेत्र का सुनियोजित रिकॉर्ड रखा जाना है, जिससे प्रदेश के 43250 गॉवों में आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

भामाशाह योजना (ग्रामीण विकास)

- सभी राजकीय योजनाओं के नकद और गैर-नकद लाभ को प्रत्येक लाभार्थी को सीधा पारदर्शी रूप से पहुँचाना।
- राशन कार्ड, पेंशन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति जैसे लाभार्थियों को भी सम्मिलित नहीं करना।
- मार्च, 2015 तक प्रदेश की सभी महिलाओं का बायोमैट्रिक डाटा सरकार के पास उपलब्ध करवाना।
- योजना की पात्रता :-
- राज्य की पात्र महिलाएँ।
- भामाशाह कार्ड के लिए पंजीकरण कराना जरूरी।
- इस योजना के तहत परिवार प्रमुख महिला सदस्य को बायोमैट्रिक कार्ड जारी किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राज्य में **''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान''** वर्ष 1999-2000 में केवल 4 जिलों में प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2005-06 से यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- 1 अप्रैल, 2012 से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम ''निर्मल भारत अभियान'' कर दिया गया।
- 2 अक्टूबर, 2014 से इसे ''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'' का नाम दिया गया।

उद्देश्य :-

- इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गॉधी की 150वीं जयंती -2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है।

- माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा वर्ष 2017-18 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने की घोषणा की गई हैं।

प्रावधान :-

- व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL) इकाइयों के निर्माण एवं उपयोग करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 12000/- (केन्द्र 75 प्रतिशत यानि रू 9000/- एवं राज्य 25 प्रतिशत यानि रू 3000/-) दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता :-

- सभी बीपीएल परिवार तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले अजा. अजजा लद्यु एवं सीमान्त किसानों, वास भूमि वाले, भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिला मुखिया वाले परिवार पात्र हैं।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

- प्रारम्भ 13 दिसम्बर, 2015 को CM द्वारा
- लाभ राज्य के 1 करोड परिवारों को, प्रीमियम सरकार देगी।
- योजना हेतु 167 निजी और 250 सरकारी अस्पताल अधिकृत।
- प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिन्हित सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए 30 हजार रूपये और चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 30 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा
- राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)व राष्ट्रीय बीमा योजना (RSBY) में आने वाले परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा।
- योजना का लाभ भामाशाह कार्ड / राशन कार्ड / RSBY कार्ड से मिलेगा।

भामाशाह रोजगार सृजन योजना

- 13 दिसम्बर 25 से प्रारम्भ।
- उद्देश्य-स्वंय का उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बनना।
- इस योजना में बैंको द्वारा प्रदत ऋण पर ब्याज सहायता देय होगी। प्रभावी ब्जाय दर **6 - 7%** होगी।
- इस योजना में 11000 उद्यमों के माध्यम से लगभग 44,000 व्यक्तियों को स्व रोजगार/रोजगार सजृन करने का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है।

कौशल विकास

- आरमोल के पुनर्जीवित करने का आधार→ प्रदेश के युवाओं को आजीवीका एवं कौशल विकास के अवसर व्यापक रूप से उपलब्ध कराना।
- राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीवीका विकास निगम (RSLDC) द्वारा निम्नलिखित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहें है:
  - पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
  - नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - कन्वर्जेन्स योजना
  - कौशल विकास पहल योजना
  - कौशल प्रशिक्षण हेतु विशेष योजना

भामाशाह योजना

- **15** अगस्त **2014** से प्रारम्भ
- लैंगिक समानता, वित्तीय समावेश एंव परिवार आधारित लाभों को सम्मलित करते हुए लागू की गई है।
- इसके अन्तर्गत **Direct Benefit Transfer (DBT)** योजना में पेंशन एवं **BPL** खातों में सीधे ही पैसा स्थानान्तरित करने की योजना भी प्रारम्भ की गई है।
- परिवारों को लाभ पहुँचाने हेतु लाभार्थियों के आधार नम्बर, भामाशाह **I.D** एव बैंक खाते इंटरलिंक किये जा रहें हैं।

अपना जिला-अपनी सरकार कार्यक्रम

- आमजन को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से **CM** द्वारा आरभ।
- इसके अन्तर्गत **CM** द्वारा जिलों में जनप्रतिनिधियों से मिलकर स्थानीय समस्याओं का **feedback** लेना, आमजन की समस्या सुनकर उनका निवारण, राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण करके सुधारात्मक कदम उठा रही है।
- सरकार द्वारा जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित करने की दिशा में कदम।
- इसमें **CM** व मंत्रीगण व संभागों के गाँव गाँव तक जाकर आमजन की पेशानियाँ सुनते हैं और जहाँ तक संभव हो, उनका त्वरित गति से हल निकालने का प्रयास करते है।

स्मार्ट सिटी मिशन

भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत राज्य के 4 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, एवं कोटा का चयन किया गया।

अमृत परियोजना

भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं जैसे नियामित पेयजल की आपूर्ति सीवरेज, पार्क, सार्वजनिक परिवहन की सुव्यवस्था पार्किग आदि के विकास के लिए अमृत योजना लागू की गई है।

राज्य के 29 शहरों जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, ब्यावर, हनुमानगढ़, गंगापुर सिटी, हिन्डौन सिटी, सुजानगढ़, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, भीलवाडा, श्रीगंगानगर, पाली टोंक, झुँझुनू, किशनगढ़, झालावाड में अमृत परियोजना क्रियान्वित की जाएगी।

राजस्थान अमृत योजना के अन्तर्गत

भरतपुर को नगर निगम, डेगाना, किशनगढ़ बास तथा इंटावा को नगरपालिका बनाया गया है,

मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना

यह योजना 'सत्र 2015-16' से प्रारम्भ की गई। जिसमें मेधावी छात्राओं का सम्मान किया जाता है।

कुशल मंगल कार्यक्रम

प्रदेश में हाई रिस्क प्रेगनेन्सी को चिहित कर उनका समूचित प्रबंधन करने के लिए दिनांक 11 जुलाई, 2015 को ''कुशल मंगल कार्यक्रम'' का शुभारम्भ किया गया है।

नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014

राज्य में 8 अक्टूबर, 2014 से लागू की गई। जिसमे पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों व थ्रस्ट सेक्टर्स में विनियोजन को बढावा देने हेतु विशिष्ट प्रावधान किये जाने की प्रक्रिया तथा कस्टमाईज्ड पैकेज का प्रावधान किया गया है।